fo"k; lwph

lEikndh;

बेलगाम महंगाई

प्रधानमंत्री को ज्ञापन............ 5
कांग्रेस खा गई शक्कर....... 7
गलत फैंसलों से बढ़े दाम.... 9
चीनी की कड़वाहट............... 11
चीनी के भाव बढ़ क्यों रहे... 13

लेख

गणतंत्र के छः दशक
i:Hkkr >k...................... 15
एक और विभाजन
ân;ukjk;.k nhf{kr.... 20
नेताजी की मौत का राज
fgek'k 'k[kj.............. 23

श्रद्धांजलि

ज्योति बसु............................ 22
जनेश्वर मिश्र......................... 22

अन्य

लोकमाता विजयाराजे सिंधिया.. 25
विश्वमंगल गौ–ग्राम यात्रा....... 27

प्रदेशों से

आन्ध्र प्रदेश.........'............... 19
पंजाब.................................. 21
बिहार.................................. 26
मध्यप्रदेश.............................. 28
दिल्ली.................................. 30

सम्पादक

çHkkr >k] lkln

सम्पादक मंडल

lR;iky

d- d- 'kek

lathc dekj flUgk

पृष्ठ संयोजन

/kewUæ dk'ky

सम्पर्क

Mk- eqdthZ Lefr U;kl

ih&66] lqcze.;e Hkkjrh ekxZ

ubZ fnYyh&110003

Qksu u- +91¼11½&23381428

QSDl ¼ +91¼11½&23387887

lnL;rk grq ¼ +91¼11½&23005700

सदस्यता शुल्क

okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-

e-mail address

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

जहाँ सत्य न हो वह फ्रार्म नहीं है, और जिसमें छल हो वह सत्य नहीं है।

-महाभारत ५/३५/४९

महंगाई का भूत- यूपीए सरकार यमदूत

चढ़ती कीमतों का भूत आज देश के लोगों को बुरी तरह से भयभीत कर रहा है और लोग कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार जो आम आदमी की खुशहाली का दावा करते थकती नहीं थी, के शासन में अब लोग अपनी दुर्दशा पर रोने के अलावा कोई चारा नहीं देख पा रहे हैं। प्रधान मंत्री, उनके वित्त मंत्री और कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमती सोनिया गांधी खुद ही थोड़े दिन पहले के अपने बयानों और घोषणाओं को पढ़ने का कष्ट उठा ले, जो उन्होंने 2004 से लेकर अब तक संसद के अंदर और बाहर दिए थे, तो जिन लोगों ने उन्हें सत्ता का सुख सौंपकर गद्दी पर बिठाया था, उनके सामने वे अपना मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे और वे स्वयं महसूस करेंगे कि सचमुच उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है।

अब शरद पवार जी को लीजिए जो कृषि मंत्री कम और क्रिकेट मंत्री ज्यादा हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी का उन्हें 'महंगाई मंत्री' का नाम देना, उनके पूरे व्यक्तित्व और कार्यशैली पर एकदम सही फिट बैठता है। अभी हाल में पिछले दिनों उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बारे में एक सवाल का उत्तर देते हुए कहा था कि ''मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं''। परन्तु 'ज्योतिषी न होने की बात' कह कर भी अभी दो–तीन पहले अचानक ज्योतिषी बन जाते हैं और कह देते हैं कि चीनी की कीमतें कुछ दिनों में घट जाएंगी।

फिर भी यह सब कुछ होते हुए भी हमें श्री पवार से सहमत होना पड़ता है कि वे भविष्यवक्ता नहीं है और मानना पड़ जाता है कि वह भविष्यवाणी करने वाले ऐसे महान व्यक्ति अवश्य हैं जो लोगों को कयामत का दिन जरूर दिखा देते हैं। पिछले छह महीनों से वह आम आदमी को उसकी बदहाली का आइना दिखा कर उससे कहते रहे हैं कि तैयार हो जाओ, अगले 12 महीनों में अनाज, दालों और चीनी की कीमतें आसमान छूने वाली हैं। फिर कभी लगता है कि वह 'इन्सोमनिया' अर्थात् अनिद्रा रोग से पीड़ित है। वह आज की बात कल भूल जाता है। कल की ही बात है कि उन्होंने दूध की बढ़ती कीमतों की बात कह डाली, परन्तु अगले ही दिन राजनैतिक दबाव पड़ते ही सारा दोष मीडिया के मत्थे मढ़ डाला। मजा यह है, भले ही ''अच्छे दिन भी आएंगे'', इस प्रकार की भविष्यवाणी फेल हो जाए, परन्तु 'कयामत' आकर रहेगी ''यह बात सच निकलती है। अनाज, दालों, चीनी और दूध के बारे में की गई उनकी घोषणाओं से जमाखोरों, मुनाफाखोरों और गैर कानूनी ढंग से पैसा कमाने वालों के तो वारे–न्यारे हो गए, क्योंकि पवार ने जिस क्षण ऐसी घोषणा की तो असामाजिक तत्वों ने आवश्यक चीजों का बनावटी अभाव पैदा कर खूब पैसा कमाने की जुगत ढूंढ ली।

आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा। सबसे बुरा हाल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और असंगठित क्षेत्र के दिहाड़ी पर काम करने वाले लोगों का रहा। परन्तु गरीबी रेखा से ऊपर के लोग भी महंगाई की आंच से बच नहीं पाए हैं। पहले तो आम आदमी जैसे–तैसे दाल–रोटी से गुजारा कर लेता था,

परन्तु अब यूपीए शासन में तो ये भी नसीब में नहीं– अब तो दाल–रोटी के लिए भी आम आदमी तरस रहा है।

भाजपा–नीत–एनडीए के शासन में सभी आवश्यक वस्तुएं नियंत्रण में रही थीं। अटल जी की सरकार ने चीजों की कमी कभी नहीं होने दी, कभी कालाबाजारी और मुनाफाखोरी नहीं होने दी। उन दिनों रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती थी बल्कि मांग पर ही मिल जाती थी। अब देखिए, जिस क्षण छह वर्ष पूर्व यूपीए सरकार सत्ता में आई तो हमारी अर्थव्यवस्था में मुनाफाखोरों, कालाबाजारी लोगों ने घुस कर चीजों में कमी लाकर सब कुछ तहस–नहस कर दिया। सच तो यह है, जो आज की बात नहीं, बल्कि शाश्वत सत्य बन गया है कि कांग्रेस और महंगाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

वास्तविकता यही है कि कांग्रेस के पास महंगाई रोकने की कोई नीति नहीं है। कांग्रेस दिशाहीन है जो अंधेरे में भटकती रहती है। जब कीमतें बढ़ती हैं और हाहाकार मचता है तो बिना किसी दीर्घकालीन नीति के वह हल्के–फुल्के ढंग से महंगाई रोकने का दिखावा भर करती है जिसका कोई परिणाम निकलता नहीं है और बेचारा गरीब मारा जाता है।

दुख तो यह भी है कि बढ़ती कीमतों के बारे में सरकार के सारे प्रयास कुछ ऐसे गलत आंकड़ों पर आधारित रहते हैं जिनका आम आदमी की जरूरतों से जुड़ी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। सरकार थोक मूल्यों पर निर्भर करती है जबकि आम आदमी को ये वस्तुएं खुदरा बाजार की कीमतों पर मिलती हैं। आज की कीमतों के आंकड़ों को ही देखें। मण्डियों (थोक बाजार) में आलू 7 रूपए (खुदरा 20रू.), प्याज 10 रूपए (खुदरा 10रू.), पत्तागोभी 3 रूपए (खुदरा 20रू.) और फूलगोभी 5 रूपए (खुदरा 30रू.) बिकता है। थोक बाजार पर आधारित कीमतों को लेकर भला सरकार आम आदमी को बेवकूफ बनाने के अलावा और क्या कर रही है? और इसीलिए कीमतों को रोकने के उसके प्रयास सदा निष्फल रहते हैं।

सबसे बड़ी उलझन तो इस बात से पैदा होती है कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और उनके जगजाहिर वारिस श्री राहुल गांधी इस विषय पर अटूट चुप्पी साधे बैठे हैं जिससे देश के हर आदमी को चोट पहुंचती है। श्री गांधी युवाओं को अधिकार सौंपने की रट तो लगाए रखते हैं परन्तु बढ़ती कीमतों का नजारा उनकी आंखों से ओझल रह जाता है जिसके कारण शिशुओं और युवाओं का निवाला तक छिन जाता है।

स्पष्ट है कि एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते भाजपा आम आदमी के जीवन को तबाह करने वाली आवश्यक वस्तुओं की निरंतर बढ़ती चली जा रही कीमतों पर खामोश और मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती है। अतः भाजपा संसदीय दल के चेयरमैन श्री लालकृष्ण आडवाणी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के एक शिष्टमंडल ने इस विषय पर यूपीए सरकार को कुंभकर्णी नींद से उठाने के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भाजपा नेताओं से वायदा किया कि उनकी सरकार बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक प्रभावी कदम उठाएगी। परन्तु मनमोहन सिंह सरकार को पिछले रिकार्ड को देखते हुए लोगों को इस सरकार से उम्मीद कम ही दिखाई पड़ती है।

भाजपा लगातार सभी स्तरों पर इस मुद्दे को उठा रही है। परन्तु अब और अधिक सहना असंभव लग रहा है। आम आदमी के सामने एक अलग ही किस्म का आतंक है– वह है बढ़ती कीमतों अर्थात् महंगाई का आतंक। भाजपा ने पहले ही बढ़ती कीमतों और इन्हें रोकने में यूपीए सरकार की विफलता के खिलाफ पूरे देश में सप्ताह भर का विरोध प्रगट करने की घोषणा कर दी है। आने वाले दिनों में भाजपा राष्ट्रीय स्तर से लेकर गांव स्तर तक बढ़ती कीमतों के खिलाफ निर्णायक और दीर्घकालीन लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है ताकि सरकार को आवश्यक कदम उठाने पर मजबूत किया जा सके और आम आदमी को वास्तव में राहत मिल सके। ■

भाजपा केन्द्रीय कार्यालय में दही-चूड़ा का भोज
हर्षोल्लास से मनाया गया मकर संक्रांति पर्व

सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश का पर्व है 'मकर संक्रांति'। यह भारतवासियों का प्रमुख त्योहार है। पूरे भारत में यह पर्व किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पिछले दो वर्ष से भाजपा मुख्यालय में 'मकर संक्रांति' मनाने की परंपरा शुरू हुई है। इसी क्रम में गत 21 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया गया।

इस अवसर पर दही–चूड़े, लिट्टी–चोखा और खिचड़ी का भोज हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बाळ आपटे, एनडीए के कार्यकारी संयोजक श्री शरद यादव, जद(यू) के वरिष्ठ नेता श्री केसी त्यागी, बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, राज्यसभा में पार्टी के उपनेता श्री एस.एस. अहलूवालिया, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सी. पी. ठाकुर राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद श्री रविशंकर प्रसाद, राष्ट्रीय सचिव व सांसद श्री प्रभात झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद श्री प्रकाश जावडेकर, राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी, भाजपा मुख्यालय प्रभारी श्री श्याम जाजू, बिहार सरकार में मंत्री श्री नंदकिशोर यादव एवं श्री अश्विनी चौबे, श्री देवदास आपटे, भाजपा संसदीय दल के कार्यालय सचिव श्री रामकृपाल सिन्हा, श्रीमती मृदुला सिन्हा, निवेशक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरुण सिंह एवं भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित ठाकर आदि वरिष्ठ नेताओं सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थिति रहे।

कार्यक्रम के आयोजन में भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री संजय मयूख और भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विवेक ठाकुर की भूमिका उल्लेखनीय रही। ■

महंगाई के मुद्दे पर भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन

कमरतोड़ महंगाई ने आम आदमी का जीना किया दूभर : भाजपा

आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के मसले पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के एक प्रतिनिफ्रिामंडल ने 20 जनवरी को प्रफ्रानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर इस संबंफ्रा में तत्काल कदम उठाने की मांग की। इस दौरान प्रफ्रानमंत्री ने भाजपा नेताओं को आश्वासन दिया कि वे महंगाई कम करने की दिशा में हर संभव कदम उठाएंगे। हम यहां ज्ञापन का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं:

vknj.kh; ièkkuea=h th]

देश में बढ़ रही अबाधित मूल्य वृद्धि को देखते हुए हम, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपके पास आने को मजबूर हुए हैं। सरकार द्वारा इस मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रभावी प्रयासों के अभाव में, पिछले कुल महीनों में आवश्यक वस्तुओं के दाम अप्रत्याशित स्तर पर आकाश को छूने लगे हैं। खाद्य वस्तुओं और आवश्यक जिंसों की कीमतों की स्थिति का प्रबंधन और निगरानी करने वाले सरकारी प्राधिकरण परस्पर अंतर्विरोधी अभिमत प्रकट कर रहे हैं, से स्थिति और बिगड़ी है : जैसे आपके मंत्रिमण्डल में कृषि, खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने बढ़ती खाद्य कीमतों पर चिंता व्यक्त करते हुए इसका दोष मांग–आपूर्ति में अंतर पर मढ़ दिया तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष को बढ़ता खाद्य मुद्रास्फीति चिंता का विषय नहीं लगती। यह 5 नवम्बर, 2009 के टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित हुआ है।

आर्थिक मंदी की अवधि में जब थोक मूल्य सूचकांक (WPI) नकारात्मक रहा तो बाजार में सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार इस हद तक बढ़े कि ये अधिक से अधिक परिवारों की पहुंच से बाहर हो गए। आर्थिक मंदी ने बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी के अलावा उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता को कम किया और आय को निम्न स्तर पर पहुंचाया। इस तथ्य कि दुनिया भर में खाद्य वस्तुओं के दाम अनेक महीनों से लगातार नियंत्रण में रहे, के बावजूद हमारे देश में खाद्य वस्तुओं के दाम अभी भी लगातार अपवाद रूप से बढ़ते जा रहे हैं।

इसका सबसे ज्यादा बुरा असर हमारे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा असंगठित क्षेत्रों के अधिकतर मजदूरों के परिवारों पर पड़ रहा है। जिनकी मजदूरी, एक लम्बे समय से बढ़ रही खाद्य कीमतों की तुलना में उचित अनुपात में मेल नहीं खाता है।

गेंहू, चावल, अनाज, दालों और सब्जियों के दाम अपवाद रूप से बेतहाशा बढ़े हैं। सरकारी अनुमानों के अनुसार खाद्य कीमतों में लगभग 20 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है जबकि बाजार में इस मूल्य वृद्धि का वास्तविक असर कहीं अधिक है। पिछले एक वर्ष में चीनी, दालों, आलू और प्याज के दाम बाजार में 50 से 100 प्रतिशत तक बढ़े हैं। अन्य खाद्य वस्तुओं विशेषकर डेयरी, पोल्ट्रि उत्पादों और यहां तक कि मौसमी सब्जियों के दामों में भी अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिल रही है। थोक मूल्यों के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर दिसम्बर, 2009 में 4.78 प्रतिशत से बढ़कर गत् माह 7.31 प्रतिशत हुई जो महीने–दर–महीने के आधार पर करीब 90 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्शाती है (सरकार द्वारा 14 जनवरी, 2010 को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार)। यह स्थिति किसी भी सरकार को तुरन्त कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त था कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित कर आम आदमी को इस कठिन परिस्थिति में बचाया जा सकें।

न केवल थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पर्याप्त अंतर अपितु सरकार द्वारा जारी कीमतों के आंकड़े बाजार में व्याप्त वस्तुस्थिति की पुष्टि करते है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो बाजार की स्थिति के साथ–साथ मुद्रास्फीति को मापता है, भी औद्योगिक मजदूरों और शहरी मजदूरों सहित सभी श्रेणियों में ऊंची बढ़ोतरी को दर्शा रही है। आवश्यकता है मूल्य सूचकांक और बाजार में वास्तविक कीमतों के बीच तालमेल बिठाने की।

खाद्य कीमतों को कुप्रबंधन इससे भी स्पष्ट होता है कि विभिन्न कृषि उत्पादों के भरपूर भण्डार होने के बावजूद कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।

यह चिंताजनक स्थिति है कि खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि वास्तव में आम उपयोग की उत्पादित वस्तुओं के दामों पर भी असर डालेगी। अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने वाले सरकार के विभाग इस ज्वलंत मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने में असफल रहे है। यह दिखता है कि स्थिति से निपटने के बारे में सरकार न गंभीर है न उसके पास कोई उपाय बचा है।

समय की आवश्यकता है आम आदमी को राहत पहुंचाने

के उद्देश्य से सरकार के पास समग्र खाद्य मूल्य और प्रबंधन नीति होनी चाहिए। वास्तव में, ऐसी नीति की सफलता एक ज्यादा वास्तविक सूचकांक जिसे ''खाद्य मूल्य सूचकांक'' कहा जा सकता है, जिसे सरकार नियमित रूप से जारी करे ताकि देश और जो सत्ता में हैं, उन्हें वास्तविक स्थिति का पता चल सके, से मापी जानी चाहिए। उपभोक्ता मामलों वाला विभाग जोकि उपभोक्ता कीमतों को देखता है, अपनी जिम्मेदारी निभाने में बुरी तरह असफल रहा है।

यह हताशाजनक है कि सरकार इस सम्बन्ध में असंवेदनशील बनी हुई है। खाद्य और कृषि मंत्री श्री शरद पवार के वक्तव्य कि वे ज्योतिषी नहीं हैं जो भविष्यवाणी कर सकें कि कब खाद्य कीमतें कम होगी और चीनी की खुदरा कीमतों में गिरावट के बारे में उनकी लगातार उलट–सुलट बयानबाजी राष्ट्र को किसी भी रूप में आश्वस्त नहीं करती है। उन्होंने यह भी इंगित किया है कि निकट भविष्य में अविधायी कर जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं, से मिलने वाली प्रभावी राहत आम आदमी को उपलब्ध नहीं होगी। खाद्य अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में आपूर्ति पक्ष का कुप्रबंधन सरकार की साफ असफलता है। सरकार कमी वाले क्षेत्रों का अंदाज लगा पाने में असफल रही है। जबकि सैद्धान्तिक रूप से यह उन क्षेत्रों में घरेलू उत्पाद का विस्तार करने की जरूरत बताती है लेकिन इन उपायों का असर वास्तविक स्थिति के साथ मेल नहीं खाता। घरेलू क्षमताओं को विस्तारित करने तथा आयातों के माध्यम से भी आपूर्ति पक्ष के प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की जरूरत है न कि उन्हें आपके मंत्रिमण्डलीय सहयोगियों के असंवेदनशील वक्तव्यों से प्रोत्साहित करने की। साथ ही जामखोरी और मुनाफाखोरी के विरुद्ध विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई करने हेतु सरकार में प्रशासनिक इच्छा और गंभीरता का अभाव है। यह इस तथ्य कि विभिन्न वस्तुओं जैसे चावल, आलू, प्याज के थोक और खुदरा मूल्यों में असमानता से प्रमाणित होता है जिनके दाम कृत्रिम कमी से बढ़े हैं। सरकार ने ऐसे मुद्दों से निपटने में अभी तक कोई दृढ़ निश्चय नहीं दिखाया है।

सरकार इस आशा में 'कुछ नहीं करने' की नीति अपनाए हुए है कि यह समस्या अपने आप सुलझ जाएगीं सरकार के विभिन्न विभागों में अपेक्षित आवश्यक समन्वय का अभाव साफ दिखता है। यह समय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में एक–दूसरे पर दोषारोपण करने का नहीं है। यह कदम उठाने का समय है क्योंकि मुद्रास्फीति प्रवृतियों ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। इस समस्या से निपटने में सरकार की बेरूखी के चलते हम आपके पास आने को बाध्य हुए हैं हम आशा करते हैं कि एक जिम्मेदार सरकार के रूप में, तुरन्त कदम उठाए जाएंगे जो खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी को शीघ्रता से नियंत्रित कर आम आदमी को कष्टों से निजात दिला सकें।

भवदीय,

लालकृष्ण आडवाणी नितिन गडकरी सुषमा स्वराज अरुण जेटली मुरली मनोहर जोशी
राजनाथ सिंह अनंत कुमार गोपीनाथ मुंडे एस.एस. अहलूवालिया ■

बहुत गिर गया है देश की राजनीति का स्तर : जेटली

पालिटिकल पावर तो बहुत हैं, लेकिन 60 सालों में देश की राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है। पालिटिकल पावर आज जिस तरह के लोगों के हाथ में हैं, उनके कारण राजनेताओं का कद छोटा पड़ गया है। विचारधारा की राजनीति, प्रतिबद्धता की राजनीति का स्थान परिवार और उपनाम (सरनेम) ने ले लिया है। इसमें भी बहुत ओछापन आ गया है।

U;k;ikfydk % देश की न्यायपालिका स्वतंत्र रही है, जो एक अच्छी बात रही है। लेकिन धीरे–धीरे इस क्षेत्र में नैतिकता और बौद्धिकता के स्तर में ह्रास हुआ है।

ehfM;k % आज पत्रकारिता का वह स्वरूप नहीं रहा जो पहले था। जब से देश के भीतर चौबीस घंटे वाले न्यूज चैनल आए हैं, उसमें हल्कापन आ गया है।

vFk0;oLFkk % आज हम तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी अवश्य है, लेकिन देश में 90 के दशक के बजाय 70 के देश में उदारीकरण किया जाता तो देश की दशा–दिशा ही अलग ही होती।

lqj{kk % छह दशक पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कश्मीर मसले पर जो भूल की थी उसकी कीमत देश 60 साल बाद भी चुका रहा है। देश की सुरक्षा काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। लेकिन यह सकारात्मक बात है कि तमाम दिक्कतों और समस्याओं के बाद भी देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत बनी हुई हैं।

;qok usr`Ro % दुनिया भर में विभिन्न देशों की कमान 40–50 साल के लोगों के हाथों में है। 60 साल के सफर के बाद हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए।

जभास्कर के बातचीत के आफ़ार परफ ■

कांग्रेस खा गई शक्कर पी गई तेल

& jktho lpku

मनमोहन सिंह इंदिरा गांधी सरीखे नहीं हैं और हो भी नहीं सकते, लेकिन उनका शासन इंदिरा गांधी के उन दिनों की याद दिला रहा है जब वह इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा वाले भाव से ग्रस्त थीं। भूतल परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर जिस तरह हर 25 किलोमीटर पर सोनिया–मनमोहन सिंह के फोटो लगाने की तैयारी कर रहा है उससे इसी की पुष्टि होती है कि इंदिरा इज इंडिया..सरीखे युग की वापसी हो गई है। एक अनुमान के अनुसार राजमार्गों पर सोनिया–मनमोहन सिंह के फोटो लगाने पर 14 से 25 करोड़ रुपये के आसपास धन खर्च होगा। राजमार्ग प्राधिकरण ने सफाई दी है कि सोनिया–मनमोहन के फोटो टांगने पर जो रकम खर्च होगी वह सरकार के खजाने से नहीं, बल्कि सड़क बनाने वाली कंपनियों द्वारा खर्च की जाएगी। यह तो और भी बुरा काम है। इसका सीधा मतलब है कि इन कंपनियों पर इसके लिए दबाव बनाया गया है कि वे अपनी जेब से पैसे खर्च कर सोनिया–मनमोहन के फोटो राजमार्गों पर सजाएं। इससे यह कहीं अच्छे से पता चल रहा है कि आम आदमी के साथ का दम भरने वाली सरकार के पास इस तबके की चिंता करने की भी फुर्सत नहीं रह गई है–और वह भी तब जब चीनी 50 और दालें 100 रुपये किलो बिक रही हैं। जाहिर है कि यदि मौजूदा हालात में खा गई शक्कर पी गई तेल, यह देखो कांग्रेस का खेल.. जैसे नारे लगाए जाएं तो अनुचित न होगा। यदि गृहमंत्री पी चिदंबरम और मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को छोड़ दिया जाए तो यह जानना कठिन है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत उनके शेष मंत्री क्या कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब तब नहीं मिल रहा जब मनमोहन सिंह को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं कि झारखंड में कांग्रेस सरकार क्यों नहीं बना सकी अथवा जगनमोहन रेड्डी पर लगाम कैसे लगाई जाए?

समस्या यह है कि आर्थिक विकास दर से रीझे चंद बुद्धिजीवियों द्वारा देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि मनमोहन जैसी मन मोहने वाली सरकार का कोई जोड़ नहीं। चूंकि विपक्ष बिखराव से ग्रस्त है और संप्रग सरकार की आलोचना करना वर्जित कृत्य करार दिया गया है इसलिए कोई भी इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं कि विदेश नीति से लेकर अर्थनीति तक के प्रत्येक मोर्चे पर केंद्रीय सत्ता कितनी विफल है। महंगाई चरम सीमा को छूने के बाद भी जिस तरह थमने का नाम नहीं ले रही उससे केंद्रीय सत्ता को चिंतित होना चाहिए, लेकिन ऐसे संकेत तक नहीं नजर आते कि उसके लिए यह चिंताजनक मसला है। दालों, चीनी एवं अन्य खाद्य सामग्री के बेतहाशा बढ़ते मूल्यों के लिए उसके पास न केवल तरह–तरह के बहाने मौजूद हैं, बल्कि यह दो टूक जवाब भी कि महंगाई का सामना करने के अलावा और कोई उपाय नहीं।

खाद्य पदार्थों की कमी के लिए कभी कम उत्पादन को जिम्मेदार बनाया जाता है, कभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी को और कभी राज्य सरकारों के उस रवैये को जिसके तहत जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में आनाकानी की जा रही है। यदि महंगाई का कारण जमाखोरी है तो फिर कम पैदावार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी का रोना क्यों रोया जाता है? सवाल यह भी है कि यदि महंगाई के लिए ये सभी कारक जिम्मेदार हैं तो फिर केंद्रीय सत्ता किस मर्ज की दवा हैघ यथार्थ यह है कि केंद्रीय सत्ता इतनी नाकारा है कि वह न तो कम पैदावार का अनुमान लगा सकी, न समय रहते दालों–चीनी आदि का आयात कर सकी। कहने को एक कृषि एवं खाद्य मंत्रालय है, लेकिन उसे न तो कृषि से मतलब है और न ही खाद्य संकट की चिंता करने से। देश यह भी महसूस कर रहा है कि मनमोहन का शरद पवार पर कोई जोर नहीं और शरद पवार को मनमोहन सिंह की कोई परवाह नहीं। शरद पवार जितने निरंकुश हैं, मनमोहन सिंह अपने निरंकुश मंत्रियों पर लगाम लगाने में

खाद्य पदार्थों की कमी के लिए कभी कम उत्पादन को जिम्मेदार बनाया जाता है, कभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी को और कभी राज्य सरकारों के उस रवैये को जिसके तहत जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में आनाकानी की जा रही है। यदि महंगाई का कारण जमाखोरी है तो फिर कम पैदावार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी का रोना क्यों रोया जाता है?

उतने ही अक्षम हैं। वह किसी सेमिनार, सभा, सम्मेलन में भाषण देने के लिए ही अधिक स्वतंत्र–सक्षम नजर आते हैं। कोई नहीं जानता–शायद मनमोहन सिंह भी नहीं कि उन समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है जो राष्ट्र के समक्ष मुंह बाए खड़ी हैं। चीन, पाकिस्तान तो दूर रहा, नेपाल और श्रीलंका तक पर भारत सरकार दबाव बनाने में अक्षम है। श्रीलंका में लाखों तमिलों के साथ भेड़–बकरियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन प्रवासी सम्मेलन में उनकी चर्चा तक नहीं की गई। इसमें संदेह नहीं कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मनमोहन सिंह की विद्वता–विनम्रता का उल्लेख होता है, लेकिन लाख टके का सवाल है कि इससे भारत की जनता को हासिल क्या हो रहा हैघ् मनमोहन सिंह सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सौ दिन के एजेंडे की घोषणा करने और फिर उसकी कामयाबी का ढिंढोरा पीटने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसे सक्षम, सक्रिय और संवेदनशील सरकार के खांचे में फिट किया जा सके।

यदि संप्रग सरकार का शेष कार्यकाल वैसे ही चलना है जैसे अब तक चला है तो उससे देश का मोह भंग होना तो तय है ही, देश का गंभीर समस्याओं से घिरना भी सुनिश्चित है और इसकी बानगी तेलंगाना मुद्दे पर केंद्र सरकार की गफलत से मिलती है। इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि सामाजिक ताने–बाने को छिन्न–भिन्न करने वाली ताकतों के सामने मनमोहन सरकार असहाय ही अधिक है। मनमोहन सरकार एक सूरत में ही सही तरह चल सकती है जब आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां समाप्त हो जाएं, देश को नुकसान पहुंचाने वाली बाहरी ताकतें शांत हो जाएं, मानसून मेहरबानी दिखाता रहे और न्यायपालिका अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में सफल हो जाए। दुर्भाग्य से ऐसा कुछ होने के आसार दूर–दूर तक नहीं हैं और आम चुनाव आने में अभी चार वर्ष से अधिक का समय शेष है। क्या तब तक ऐसे ही चलेगाघ् इस सवाल पर विपक्ष विचार करे या न करे, आम जनता को अवश्य करना चाहिए। ■

जलेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैंघ

शरद पवार इस्तीफा दें : राजीव प्रताप रूडी

भारतीय जनता पार्टी के राष्टीय श्वक्ता व सांसद, श्री राजीव श्ताप रूडी द्वारा 11 फरवरी, 2010 को जारी श्रेस विज्ञप्ति

वर्तमान सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह से विफल रही है और वह जनता के सामने बहाना बनाकर अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोग एक–दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। और महंगाई के लिए कहीं न कहीं राज्यों को जिम्मेदार बता रहे हैं। लेकिन, वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियां किसान और मजदूर विरोधी और जमाखोरों और बिचोलियों

को फायदा पहुंचाने वाली है। अगर हम सरकार के कार्यकाल को देखें तो यह आरोप सही साबित होता है। यह सरकार किसान विरोधी है, क्योंकि यह सरकार देश के किसान से गेहूं 9.50/– रूपए प्रतिकिलो खरीद रही है और विदेश किसान से 16/– रूपए प्रतिकिलो खरीद रही है। पिछले साल अरहर दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 23 रूपए था, विदेशी किसान को 26 रूपए दाम देकर दाल का आयात किया गया था। आज किसान से 10 रूपए प्रति किलो के हिसाब से धान खरीदा जा रहा है और ग्राहक से 40 रूपए प्रति किलो वसूला जा रहा है। कांग्रेस सरकार मार्च 2009 तक यह घोषणा करती रही कि देश में चीनी के पर्याप्त भंडार है और दो साल तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, 48 लाख टन चीनी 12/– रूपए प्रति किलो के हिसाब से निर्यात की गई। पिछले 6 महीनों में सरकार को अचानक याद आता है कि चीनी की किल्लत होने वाली है। और आज वही चीनी 30 रूपए प्रति किलो के हिसाब से आयात हो रही है। सरकार आम आदमी की विरोधी है। इसलिए सरकार विदेशी ग्राहक को 12 रूपए में चीनी बेच रही है और वहीं देशी ग्राहक से 44 रूपए वसूल रही है।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूण है कि बिचोलिए और जमाखोर आज तय कर रहे हैं चीनी, चावल, दाल, गेहूं का कब आयात करना है और कब निर्यात।

देश के किसान और गरीब आदमी को लूटा जा रहा है। कांग्रेस चुनाव में वोट आम आदमी के नाम पर लेती है लेकिन, सत्ता में आते ही सट्टोरियों और मुनाफाखोरों को फायदा पहुंचाती है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि श्री शरद पवार अविलंब इस्तीफा दे और साथ ही यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि आखिर इस देश का किसान और गरीब आदमी कब तक लुटता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम महंगाई के खिलाफ संसद में और संसद के बाहर सरकार के काले कारनामों को जनता के बीच ले जाएंगे और जब तक कांग्रेस सरकार महंगाई कम नहीं करती तब तक हम गरीब, किसान और मजदूर के अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ■

गलत फैसलों से बढ़े चीनी के दाम

& d|.kky ck l

V र्थशास्त्र का सामान्य सिद्धांत है कि अगर किसी जिंस की कमी होती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं।

अगर चीनी जैसी आवश्यक जिंस की बात हो, जिसकी आपूर्ति में वैश्विक कमी है और दो प्रमुख उत्पादन केंद्रों पर उत्पादन में कमी आई हो तो कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी स्वाभाविक है।

भारत में 1972 के बाद से सबसे खराब मॉनसून पिछले साल रहा और 2009 के अंतिम महीनों में ब्राजील में गन्ने की खेती बुरी तरह खराब हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 12 महीनों में चीनी की कीमतें 30 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं।

पिछले साल दुनिया में करीब 110 लाख टन चीनी की कमी हुई। यही कारण है कि एलआईएफएफई में सफेद चीनी के मार्च महीने के वायदा दाम 730 से 748 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गए। वहीं आईसीई में कच्ची चीनी के दाम 27.91 सेंट से 28.95 सेंट प्रति पाउंड के बीच हैं।

नए साल और क्रिसमस के समय कारोबारी बंदी के बाद जब जनवरी 2009 में बाजार खुले थे तो एलआईएफएफई में मार्च का सौदा सफेद चीनी के लिए 327.80 डॉलर प्रति टन और आईसीई में कच्ची चीनी के सौदे 11.82 सेंट प्रति पाउंड पर हुए थे।

2008–09 में भारत में फसल की कमी होने की प्रमुख वजह यह थी कि किसानों ने गन्ने को लाभ की खेती नहीं समझा और वे अन्य फसलों की ओर आकर्षित हुए। गुड़ और खांडसारी इकाइयों ने देखा कि भारत केवल 146 लाख टन चीनी बना रहा है, जबकि जरूरत 225 लाख टन चीनी की है।

उन दिनों शुरुआती स्टॉक पर्याप्त था, साथ ही आयात भी हुआ। लेकिन अब स्थिति यह है कि दुनिया जानती है कि हमारे देश में चीनी की कमी है और बड़े पैमाने पर आयात करना पड़ेगा। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्ची और सफेद दोनों ही चीनी का बड़े पैमाने पर किसी भी कीमत पर आयात करना होगा।

> *चीनी की बढ़ती कीमतों के संकट को देखते हुए ृषि मंत्री शरद पवार ने हकीकत को स्वीकार किया और कहा, 'हमने जब चीनी का आयात करने का फैसला किया तो मात्रा पर विचार करते हुए इसकी वैक्ृिवक कीमतें बहुत तेजी से बढ़ गईं और जब अतिरित्त उत्पादन के चलते निर्यात की स्थिति आती है तो चीनी की वैक्ृिवक कीमतें फ्राराशायी हो जाती हैं।'*

चीनी की बढ़ती कीमतों के संकट को देखते हुए कृषि मंत्री शरद पवार ने हकीकत को स्वीकार किया और कहा, 'हमने जब चीनी का आयात करने का फैसला किया तो मात्रा पर विचार करते हुए इसकी वैश्विक कीमतें बहुत तेजी से बढ़ गईं और जब अतिरिक्त उत्पादन के चलते निर्यात की स्थिति आती है तो चीनी की वैश्विक कीमतें धराशायी हो जाती हैं।'

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली ने चीनी निर्यात दो सीजन पहले रोक दिया था और उसके बाद से वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़नी शुरू हुईं। वैश्विक बाजार में यह भय हुआ कि भारत में घरेलू उत्पादन कम हो गया है। उस समय पाकिस्तानी बाजार को एक अवसर मिला था। भारत में 2006–07 सत्र में रिकॉर्ड 283.3 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था और उसके अगले साल भी 263.3 लाख टन चीनी का बंपर उत्पादन हुआ।

निर्यात बंद करने के गलत फैसले के चलते भी आज के संकट में अहम भूमिका निभाई। इसे व्यापक तौर पर देखे जाने की जरूरत है। अतिरिक्त उत्पादन और निर्यात के रास्ते बंद होने की वजह से घरेलू बाजार में अतिरिक्त चीनी हो गई और कुछ महीनों तक स्थिति ऐसी हो गई कि मिलों को इतने कम दाम पर चीनी की बिक्री करनी पड़ी कि उससे गन्ना खरीदने की लागत भी नहीं निकलती थी।

इसके साथ ही एक अन्य तथ्य भी महत्वपूर्ण रहा। कमोबेश सभी मिलें डिफाल्टर हो गईं और वे गन्ने का भुगतान करने में अक्षम साबित होने लगीं। हालांकि नियमों में स्पष्ट है कि चीनी उद्योग को 14 दिन के भीतर किसानों के बकाये का भुगतान करना है।

एक ऐसी भी स्थिति आई कि मिलों पर गन्ने का बकाया बढ़कर 9000 करोड़ रुपये हो गया। सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था, जिससे उद्योग को बचाने के लिए वह अपनाए। सभी मिलों की बैलेंस शीट खतरे के निशान पर थी। उद्योग के अधिकारी ओम धानुका कहते हैं कि किसान इस कदर प्रभावित हुए

थे कि उन्हें गन्ने का दूसरा विकल्प मजबूरी में चुनना पड़ा।

धानुका ने कहा, 'न केवल गन्ने की बुआई का क्षेत्रफल 2006–07 के 5.515 मिलियन हेक्टेयर से गिरकर पिछले साल 4.395 मिलियन हेक्टेयर रह गया, बल्कि उद्योग जगत को इस समय चीनी के अन्य विकल्पों को तलाशना पड़ा। इसमें एक बुराई और जुड़ गई कि 2009 में मौसम बहुत खराब रहा।श

लेकिन इस समय चीनी के दाम ज्यादा हैं। साथ ही किसानों को लाभकारी मूल्य मिलने के अधिकार का हर राजनीतिक दल समर्थन कर रहा है। इन सब तथ्यों से एक बार फिर किसानों को गन्ने का रुख करने का प्रोत्साहन मिला है। लेकिन किस्मों के मुताबिक गन्ने की फसल तैयार होने में 12–15 महीने समय लगता है।

इस समय जो स्थिति है, उसका गन्ना उत्पादन में फायदा 2010–11 सत्र में नजर आएगा, जब हमारा चीनी उत्पादन 240 लाख टन हो जाएगा और उस समय आयात गायब हो जाएगा। ब्राजील में सितंबर और दिसंबर में हुई भारी बारिश की वजह से गन्ने की फसल खराब हो गई है, इसका फायदा हमें 2010–11 (मई से अप्रैल) सत्र में मिलेगा।

अब उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान भारत में बंपर उत्पादन होगा और करीब 5900 लाख टन गन्ने का उत्पादन इस दौरान हो सकता है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है, श्चीनी की रिकॉर्ड कीमतों की वजह से ब्राजील में अगेती किस्म की फसल का उत्पादन मार्च में हो सकता है, जो सामान्यतया मई में होता है।' इंटरनैशनल शुगर आर्गेनाइजेशन का कहना है कि अगले सत्र में चीनी का उत्पादन कुल मांग की तुलना में 10 लाख टन ज्यादा हो सकता है।

कुल मिलाकर इसका मतलब यह है कि आम लोगों को चीनी की अनपेक्षित कीमतों का भुगतान करना पड़ रहा है। नए सत्र में ब्राजील की चीनी बाजार में होगी और 2010 के पहली छमाही के दौरान कीमतें उफान पर ही रहेंगी। .षि जिंस के ज्यादातर विश्लेषकों का यह मानना है कि आईसीई वायदा कम होकर 17 सेंट प्रति पाउंड तक आएगा। ■

प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमण्डल है जिम्मेदार : पवार

महंगाई पर मनमोहन को लपेटा

देश में बढ़ती महंगाई को लेकर निशाने पर आए केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल को अपने साथ लपेट लिया है। पवार ने कहा कि कीमतों पर नीतिगत निर्णय मंत्रिमंडल में सामूहिक रूप से लिया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। सरकार का पता नहीं, लेकिन पवार की यह दलील मुख्य विपक्षी दल भाजपा के गले नहीं उतर रही। इस मुद्दे पर पार्टी उन्हें बख्शने के मूड में कतई नहीं है। भाजपा ने प्रधानमंत्री और सरकार से मांग की कि महंगाई पर नियंत्रण पाने में नाकाम कृषि मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। महंगाई यूपीए–1 सरकार में थी, लेकिन यूपीए–2 सरकार के सत्ता संभालते ही इसको पंख लग गए हैं। शायद ही कोई खाद्य पदार्थ है जो पिछले कुछ महीनों में महंगा न हुआ हो। हालात यह हैं कि घर–घर में बहुतायत से खाई जाने वाली अरहर की दाल सौ रुपए प्रति किलो के पार जाने को बेताब है तो चीनी की कीमत पिछले दस दिनों में 10 रुपए प्रति किलो बढ़ चुकी है और खुदरा बाजार में वह 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसके अलावा कृषि मंत्री शरद पवार हाल ही में दूध के दामों में भी बढ़ोतरी के संकेत दे चुके हैं। यानि आने वाले दिनों में दूध भी पांच से दस रुपए प्रति लीटर महंगा हो सकता है। यही हाल दूसरे खाद्य पदार्थो का भी है। महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है और कृषि मंत्री आरोप प्रत्यारोप के खेल में उलझे हैं। पहले उन्होंने इसके लिए राज्यों और उनकी वितरण प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन जब राज्यों ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया तो अब वह इसके लिए प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में शामिल होने वाले वह अकेले व्यक्ति नहीं है। मूल्य नीति पर प्रधानमंत्री और हम सब मिलकर निर्णय करते हैं। इसमें विशेषज्ञों की एक समिति होती है जो मंत्रिमंडल को सलाह देती है और मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय करता है। पवार से कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से सहयोग नहीं मिलने के आरोपों के बारे में पूछा गया था। चीनी के बढ़ते दामों पर उन्होंने सफाई दी कि चीन जैसे बड़े देशों ने बड़े पैमाने पर चीनी की खरीद की है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम काफी बढ़ गए हैं।

शरद पवार कोई भी सफाई क्यों न दें, लेकिन विपक्षी भाजपा उससे कतई सहमत नहीं है। पार्टी ने पवार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। राजग कार्यकाल के समय से महंगाई की तुलना करते हुए पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार जनता की बजाये सटोरियों और जमाखोरों के लिए राह बना रही है। महंगाई के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन कर रही भाजपा ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को याद दिलाया कि सरकार बनने से पहले उन्होंने सौ दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन महंगाई कम होने की बजाये लगातार बढ़ रही है। राजग कार्यकाल में अकाल पड़ने के बावजूद जहां गेहूं की कीमत नौ रुपए और चावल 10 रुपए किलो था, वहीं आज इसकी कीमत तीन से चार गुना ज्यादा है। एफसीआई के गोदाम भरे होने के बावजूद सरकार ने बाहर से 19 रुपए किलो की दर पर गेहूं आयात किया। यह गेहूं ग्राहकों को 24 रुपए प्रति किलो बेचा गया। 2008 में चीनी का निर्यात किया गया और छह महीने के अंदर अचानक इसकी किल्लत हो गई। जो चीनी राजग काल में 14 रुपए थी अब 50 रुपए प्रति किलो है। दाल में भी काला है। पवार इसके प्रति गंभीर होने की बजाये हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। रविशंकर ने कहा कि सरकार महंगाई से पीडित लोगों के साथ मजाक कर रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार पवार को बर्खास्त करे। ■

पवार क्यों नहीं कम कर पा रहे हैं चीनी की कड़वाहट

& vkfnfr QM.kh l

dन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार नाराज हैं, और इसकी वजह जायज है।

वह अपने नियमित काम में व्यस्त थे कि इसी बीच चीनी 50 रुपये प्रति किलोग्राम की ऊंचाई तक जा पहुंची और उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मिल मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया जो उनके मित्र हैं।

दूसरी पार्टियों में मौजूद मित्र भी कह रहे हैं : माफ करना मित्र, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर तुम्हें चीजों को समझना चाहिए था। हाल के समय में कृषि मंत्री पर ज्यादा तल्खी के साथ हमला हुआ है। महंगाई में बढ़ोतरी के लिए खाद्यान्न में आई महंगाई अकेले ही महत्त्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है।

खाद्यान्न की कीमतें, खास तौर पर चीनी की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। चूंकि चीनी की कीमत में बढ़ोतरी की वजह आपूर्ति से संबंधित है और उत्पादन चक्रीय होता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी कहते हैं कि पवार को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी और उन्हें पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था। इसके बदले भारत दुनिया के दूसरे देशों से चीनी खरीदने जा रहा है और आपूर्तिकर्ताओं से सिफारिश कर रहा है कि यह अनुपयुक्त नहीं है।

पवार की राजनीतिक किस्मत चीनी के चक्रीय उत्पादन की तरह ही है। इसमें गिरावट साल 2005 की शुरुआत में तब आरंभ हुई जब शरद पवार ने एक बार फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस साल सबसे ज्यादा समय लॉबिंग करने, अपनी स्थिति को एकीकृत करने और फिर बीसीसीआई को जगमोहन डालमिया के जाल के मुक्त करने की कोशिश में व्यतीत हुआ।

इसी व्यक्ति की वजह से पवार इससे पहले बीसीसीआई का चुनाव नहीं जीत पाए थे। क्रिकेट की राजनीति में शामिल रहे लोग जानते हैं कि क्रिकेट प्रशासन के शिखर पर पहुंचना काफी मुश्किल काम है और वहां टिके रहना और भी मुश्किल। समझा जाता है कि इसने काफी हद तक पवार का समय और ध्यान खींचा। अब वह आईसीसी के प्रेजिडेंट इन वेटिंग हैं। यह भी काफी समय लेगा।

खाद्या" की उच्च कीमतों के गोरखफ्रांफ्रो पर ंषि मंत्री से पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने बल्लेबाजी कर दी। पवार ने कहा कि मैं ज्योतिषी नह} हूं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा – मैं नह} जानता कि चीनी की कीमतें कब कम होंगी।

तब से अब तक आम चुनाव व महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के बीच यह जंगली सवारी जैसा रहा है। दिसंबर 2009 में शरद पवार लगातार चौथी बार अपनी पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। बढ़ती कीमतों की बाबत उनकी पार्टी भी सतर्क व संवेदनशील है और पार्टी ने यह प्रस्ताव पारित किया है : कीमतों में असामान्य उछाल ने आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी की है।

देश के कुछ निश्चित इलाकों में सूखे जैसी स्थिति ने सब्जियों समेत आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को प्रोत्साहित किया है। लेकिन सरकार गंभीरता से स्थिति की निगरानी कर रही है ताकि उचित कीमत पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सके। यह जन वितरण प्रणाली को मजबूत करने के अलावा राज्य सरकार द्वारा बाजार में और हस्तक्षेप का समर्थन करता है।

जन वितरण प्रणाली को मजबूत कर आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर कुछ हद तक लगाम लगाया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमत में बढ़ोतरी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए। इस बीच, क्रिकेट प्रबंधन भी एक समस्या थी।

खाद्यान्न की उच्च कीमतों के गोरखधंधे पर कृषि मंत्री से पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने बल्लेबाजी कर दी। पवार ने कहा कि मैं ज्योतिषी नहीं हूं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा – मैं नहीं जानता कि चीनी की कीमतें कब कम होंगी। हालांकि क्रिकेट के बारे में उनके पास बहुत कुछ था। उन्होंने कहा कि फिरोज शाह कोटला मैदान पर मैच कराने की अनुमति की बाबत आईसीसी अगले हफ्ते फैसला लेगा।

इसके दो दिन पहले आईसीसी के प्रेजिडेंट ने कहा था कि वह उस मैदान पर वर्ल्ड कप के मैच पर पाबंदी लगाने के पक्ष में नहीं हैं। हालांकि आईसीसी के मैच रेफरी एलन हर्स्ट ने इसे अनफिट बताया था। पिछले महीने भारत–श्रीलंका मैच को रद्द करते हुए उन्होंने यह बात कही थी। जनवरी में ढाका में आयोजित वर्ल्ड कप आयोजन समिति की अध्यक्षता करने के बाद पवार ने कहा था कि इस मामले में मैं किसी तरह की राय नहीं देने जा रहा।

आईसीसी को इस बाबत फैसला लेना है और यह प्रक्रिया चल रही है। बीसीसीआई को उम्मीद है कि अगले महीने या दो महीने में आईसीसी से शायद प्रत्युत्तर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस उपमहाद्वीप का यह सबसे बड़ा क्रिकेट आयोजन है और मुझे

विश्वास है कि जिस तरह की तैयारी हो रही है उसे देखते हुए यह पूरी तरह सफल रहेगा और सुरक्षा का कोई मुद्दा इसके आड़े नहीं आएगा। भारत व श्रीलंका को विश्व कप के आयोजन का अनुभव है और यह बड़ा आयोजन होगा। वास्तव मेंघ और चीनी की कीमत भी जल्दी ही नीचे आ जाएगी? यह याद दिलाना फायदेमंद रहेगा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के पिछले कार्यकाल में गेहूं के साथ क्या हुआ था। तब भी पवार ही कृषि व खाद्य मंत्री थे।

अक्टूबर–नवंबर 2005 में स्पष्ट हो गया था कि भारत गेहूं की किल्लत के कगार पर खड़ा था। प्रधानमंत्री ने संकेत देना शुरू कर दिया था कि कृषि मंत्रालय को खुद ही गेहूं आयात की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि भारतीय खाद्य निगम की तरफ से पिछले साल खरीद में काफी कमी आई थी और वैश्विक स्तर पर गेहूं का संकट था। इसके बाद सरकार ने आखिर क्या किया?

कृषि मंत्रालय ने इस पर विचार किया। एक बार फिर विचार किया और एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गेहूं की किल्लत की बाबत और इससे जुड़े खतरे के बारे में दिसंबर 2004 में ही संकेत दे दिया था। लेकिन आयात का काम फरवरी 2005 में शुरू हुआ। गेहूं के कारोबारियों ने उन शुल्कों से इनकार किया जो कि इस अवधि के दौरान कीमतें बढ़ने से पैदा हुई थी। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा का भंडारण हम कहां करेंगे।

खराब स्थितियां बरकरार रहीं। कुछ विदेशी इकाइयों की तरफ से सुझाव आया कि भारत द्वारा आयातित गेहूं का मानक दूसरी विदेशी इकाइयों की मदद करने के लिए बदल दिया गया था। मंत्रालय को अहसास हुआ कि आयात किया गया गेहूं पर्याप्त नहीं है, लिहाजा दूसरी श्रृंखला के लिए निविदा जारी की गई।

इससे पहले कि यह निविदा खोली जाती, कृषि मंत्री ने ऐलान किया कि निजी क्षेत्र के आयातक के लिए आयात शुल्क 50 फीसदी से घटाकर शून्य किया जाएगा। भारत की तरफ से खरीदारों के आने की भनक से वैश्विक निविदाकर्ताओं ने कीमतें बढ़ा दीं। चीनी के साथ इस समय क्या होने जा रहा है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।■

स्वार्थी लोगों ने बढ़ाई महंगाई

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ती महंगाई के मामले में 18 जनवरी को शुगर लॉबी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की लापरवाही और कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण महंगाई बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से सवाल किया कि दस दिन में महंगाई कम करने की बात करने वाले बीते छह महीने से कहां थे? मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों के सिलसिले में इंदौर प्रवास पर आए थे। विमानतल पर उन्होंने कहा केंद्र ने महंगाई से आम आदमी को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। सरकार सोती रही और महंगाई बढ़ती रही। जब–जब गंभीरता से बात उठाई, केंद्र ने राज्य पर ठीकरा फोड़ कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली। प्रदेश को तो शकर का वह कोटा भी पूरा आवंटित नहीं किया जो राशन दुकान के लिए निर्धारित है।

चिंता नहीं करें, प्रदेश में एक भी माफिया नहीं रहेगा

मुख्यमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि जमीन घोटालों में लिप्त लोगों के खिलाफ अभियान सतत और सख्ती से चलेगा। उन्होंने भूमाफिया के साथ वनमाफिया का जिक्र आने पर स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की चिंता न करें, प्रदेश में एक भी माफिया नहीं रहेगा। फिर चाहे वह भूमाफिया हो या वनमाफिया।

ओमेक्स सिटी में परिषद बैठक

इंदौर में अगले महीने होने जा रही भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बायपास पर ओमेक्स सिटी ग्राउंड पर होगी। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और राष्ट्रीय महासचिव अनंतकुमार की अगुआई में लिया गया।

17 से 19 फरवरी तक चलने वाली इस बैठक में लालकृष्ण आडवाणी सहित भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश इकाइयां, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष व महामंत्री समेत पांच हजार से ज्यादा नेता शामिल होंगे। सभी किसी होटल या क्लब–गार्डन के बजाय बैठक स्थल पर ही टेंट में ठहरेंगे। बैठक में नए अध्यक्ष नितिन गडकरी की ताजपोशी की विधिवत प्रक्रिया पूरी होगी। ■

भाजपा खेलकूद प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन

भारतीय जनता पार्टी खेलकूद प्रकोष्ठ द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी का अभिनंदन खेलकूद प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री कीर्ति आजाद के नेतृत्व में सैकड़ों खिलाड़ियों ने 11, अशोक रोड पर किया। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने प्रतिभावान खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए भरसक प्रयास करती रही है और करती रहेगी। खेल भावना ही सही राष्ट्र भक्ति है। जिस एकता का परिचय खिलाड़ी देते है वह समाज के लिए प्रेरक है। किसी भी राष्ट्र के विकास की बुनियाद खेल और खिलाड़ी का विकास भी है। अतः खेल के क्षेत्र में प्रगति भी हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इससे सामाजिक विषमता का भी निदान होगा।

श्री कीर्ति आजाद, सांसद व पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि कॉमनवेल्थ खेलों की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही। वह खिलाड़ियों के प्रति लापरवाह है। आये दिन खबर मिल रही है कि कॉमनवेल्थ खेलों की तैयारी पूरी नहीं है। इस असवर पर खेलकूद प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सह–संयोजक श्री सुनील गुप्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी को विश्वास दिलाया कि भाजपा खेलकूद प्रकोष्ठ खिलाड़ियों के लिए संघर्ष करता रहेगा। इस अवसर पर श्री अशोक कुमार, श्री पंकज गौड, श्री जगत सिंह पहलवान, श्री मदन गोपाल मित्तल, श्री उत्तम कुमार रजोरिया आदि ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी का अभिनंदन किया। ■

चीनी के भाव बढ़ क्यों रहे हैं?

jktUæ gjnfu;k

vkज यदि पीड़ित असहाय किसान गन्ने की खेती से पूर्णतः हट जाए तो चीनी उद्योग चरमरा जाएगा तथा देश पूरी तरह आयात पर आश्रित हो जाएगा। फिर उपभोक्ताओं को चीनी किस भाव मिलेगी। अभी जो आम उपभोक्ता के साथ जो क्रूर मजाक हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? एक बड़ा सवाल है कि हमारी चीनी नीति कहां असफल हुई?

चीनी की रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने केंद्र सरकार को हिला दिया है। कृषि मंत्री शरद पवार कठघरे में हैं। मिलें व चीनी व्यापारी निशाने पर हैं। समस्या से तात्कालिक छुटकारा पाने के उपाय खोजे जा रहे हैं लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है कि अचानक यह समस्या आई कैसे?

हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पिपरिया से गाडरवारा जाते समय रास्ते में पड़ने वाली दो बड़ी चीनी मिलों, रामदेव शुगर मिल तथा नर्मदा शुगर मिल के सामने से मैं गुजरा। मिलों में गन्ना पेराई का यह व्यस्ततम सीजन है लेकिन पिछले सालों की तुलना में वहां एक बड़ा अंतर दिखा। मिलों के सामने गन्ने से लदी बैल गाड़ियों, ट्रैक्टर, ट्रालियों व ट्रकों की कोई रेलमपेल नहीं थी। गन्ना परिवहन से सड़कें लगभग खाली थीं। दो साल पहले मिलों के सामने सड़क पर दूर–दूर तक गन्ने से लदी ट्रैक्टर–ट्रालियों, ट्रकों व बैलगाड़ियों की लंबी–लंबी कतारें दिखती थीं लेकिन इस बार ऐसा लगता था कि जैसे अभी से गन्ना पेराई समापन पर हो। यह दृश्य वास्तव में किसानों के गन्ने की खेती से मोह भंग का है। शुगर मिल के एक संचालक विनीत माहेश्वरी के अनुसार पहले की तुलना में पिछली बार गन्ने का रकबा घटने से उन्हें मात्र 25 प्रतिशत गन्ना ही मिल पाया है।

दूसरी ओर चीनी के दामों में गजब का उछाल है। जनवरी 2009 में 22 रुपए किलो मिलने वाली चीनी 45 रुपए किलो तक पहुंच गई। बताया जाता है कि इस साल चीनी उत्पादन में कमी हो गई। तुर्रा यह कि भारत दुनिया के दस सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर है।

ब्राजील में जून 2008 में 514 लाख टन चीनी थी, वहीं हमारे देश में 355 लाख टन चीनी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि देश में चीनी का अकाल पड़ गया? हुआ यह है कि एक साल के अंदर ही भारत ने अतिरिक्त स्टाक ठिकाने लगाने के लिए 50 लाख टन चीनी का निर्यात किया। फिर उत्पादन कम होने पर 50 लाख टन चीनी का आयात किया। निर्यात के समय विश्व बाजार के भाव 230 डॉलर प्रति टन थे। जब आयात किया तो वही भाव 700 डॉलर प्रति टन के हो गए। निर्यात में भी घाटा और आयात में भी घाटा।

पड़ताल से पता चलता है कि गन्ना उत्पादन में कमी, चीनी उत्पादन में गिरावट तथा कीमतों में जो उछाल आज आया है इसकी नींव तो सन्? 2005–06 में रखी जा चुकी थी। साल दर साल के गन्ने की पैदावार, चीनी का उत्पादन व देश में घरेलू खपत के आंकड़े इस हकीकत को बयान करते हैं। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन की पत्रिका 'इंडियन शुगर' में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2005–06 में देश में कुल 232 लाख टन चीनी थी जबकि खपत 185 लाख टन की हुई। उस समय चीनी के भाव 1800 रुपए प्रति क्विंटल थे। इसमें किसान को 100 से 120 रुपए का भाव मिल रहा था।

गन्ने के उचित दाम मिलने से गन्ने का रकबा बढ़ा जिससे वर्ष 2006–07 में 319 लाख टन की उपलब्धता हो गई। इस वर्ष खपत 210 लाख टन की थी। वर्ष 07–08 में तो उत्पादन और बढ़ा जिससे देश में कुल स्टाक 355 लाख टन का हो गया जबकि मिलों के लिए घरेलू खपत का बाजार 225 लाख टन का ही था। चीनी के इस ज्यादा उत्पादन व घरेलू कम खपत से मिलों के सामने गंभीर संकट पैदा हुआ। मिलों के पास भंडारण के लिए जगह नहीं बची तथा माल की पर्याप्त बिक्री न होने से नकद राशि हाथ में नहीं आईए इससे मिल व किसान दोनों ही परेशान हो गए। बढ़े उत्पादन को ठिकाने लगाने के लिए मिलें गला काट प्रतिस्पर्धा में उतर आईं। जहां अक्टूबर 2006 में चीनी के भाव 1700 से 1800 रुपए क्विंटल थे, वहीं जनवरी 2007 से भावों का गिरना चालू हुआ व मार्च 2007 से जून 2008 यानी सवा साल तक 1300–1400 रुपए प्रति क्विंटल के रह गए। घाटे में ही सही, किसी तरह पैसा खड़ा करने के चक्कर में उत्पादकों

> ***जिस किसान ने ठंड के मौसम की कड़कड़ाती सद, गम की चिलचिलाती फ्रूप, बरसात के पानी में भीगते हुए, तीनों मौसम में खेत में रहकर बड़ी मेहनत से ग` की फसल तैयार की थी, उसकी वह फसल मिलों के गेट पर रेट के मामले में फेल हो गई। 13 रुपए किलो में बिकने वाली चीनी में किसान को जो हिस्सा मिला, वह इतना कम था कि उनकी लागत तक नह} निकली। इस कारण किसान का ग` की खेती से मोह भंग हो गया तथा उसने अन्य फसलों का रुख कर लिया। नतीजा सामने है...***

ने स्वयं प्रयास करके वर्ष 2006–07 में 18 लाख टन तथा वर्ष 2007–08 में 50 लाख टन का निर्यात किया।

जिस किसान ने ठंड के मौसम की कड़कड़ाती सर्दी, गर्मी की चिलचिलाती धूप, बरसात के पानी में भीगते हुए, तीनों मौसम में खेत में रहकर बड़ी मेहनत से गन्ने की फसल तैयार की थी, उसकी वह फसल मिलों के गेट पर रेट के मामले में फेल हो गई। 13 रुपए किलो में बिकने वाली चीनी में किसान को जो हिस्सा मिला, वह इतना कम था कि उनकी लागत तक नहीं निकली। इस कारण किसान का गन्ने की खेती से मोह भंग हो गया तथा उसने अन्य फसलों का रुख कर लिया। नतीजा सामने है कि गन्ने का रकबा घट गया। किसान तो गन्ना उगाना छोड़ सकता है पर चीनी मिलों के लिए गन्ने का विकल्प नहीं है। उद्योगपति तो मुनाफा कमाने के लिए मिल लगाता है। किसान उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है।

लेवी पर खरीदी की जो दरें सन् 2002 में रुपए 13.50 प्रतिकिलो थीं, वे आज तक यथावत हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सरकार मिलों से बीस प्रतिशत यानी 10 किलो चीनी में से 2 किलो चीनी लेवी लेती है। शेष आठ किलो चीनी उद्योगपति खुले बाजार में बेच सकता है। उसे लेवी तथा खुले बाजार के जो औसत दाम मिलते हैं, गन्ने का भाव उसी पर तय होता है। जैसे बाजार में यदि चीनी 40 रुपए किलो हो तो एक एकड़ में उत्पादित 10 किलो चीनी के दाम वैसे तो 400 रुपए होंगे पर लेवी के कारण 2 किलो के दाम 13.50 लेवी दर से 27 रुपए तथा 8 किलो 40 रुपए की दर से 320 रुपए यानी 10 किलो के कुल दाम 347 रुपए होंगे। यही दाम गन्ने के मूल्य तय करने का आधार होंगे। इससे लेवी का यह आनुपातिक बोझ किसान पर आता है।

आज यदि पीड़ित असहाय किसान गन्ने की खेती से पूर्णतः हट जाए तो चीनी उद्योग चरमरा जाएगा तथा देश पूरी तरह आयात पर आश्रित हो जाएगा। फिर उपभोक्ताओं को चीनी किस भाव मिलेगी। अभी जो आम उपभोक्ता के साथ जो क्रू र मजाक हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? एक बड़ा सवाल है कि हमारी चीनी नीति कहां असफल हुई ? चीनी उद्योग पर सरकार का नियंत्रण है। जब अधिक उत्पादन व अतिरिक्त स्टाक के कारण मिलें जब उसे ठिकाने लगाने के लिए परेशान थीं और किसान भटक रहे थे तब क्या सरकार ने कोई आकलन नहीं किया?

सन 2008–09 में गन्ने का रकबा घटने से मिलें चेतावनी दे रही थीं कि चीनी का उत्पादन कम होगा, पर गाफिल सरकार का कहना था कि चीनी का उत्पादन 220 लाख टन होगा। लेकिन पेराई के सीजन के बाद चीनी का उत्पादन 145 लाख टन पर आकर रूक गया। यह सरकारी की अदूरदर्शिता थी। यदि सरकार उस समय उस अतिरिक्त स्टाक को 13–14 रूपए के बजाय 18–20 रूपए की दर से स्वयं खरीद कर बफर स्टाक बना लेती तो किसानों को गन्ने के उचित दाम मिल जाते जिससे किसान गन्ने की खेती से नहीं हटता तथा आज उपभोक्ता को महंगी चीनी नहीं मिलती। ■

कीमत पर काबू पाने के सरकार के हर दांव को दिखाया ठेंगा

10 दिन में चीनी रुपये महंगी

चीनी की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से भाव घटने की जगह बढ़ गए। खुद सरकारी आंकड़े ही इसकी गवाही दे रहे हैं। सरकार की पहल के 10 दिनों के भीतर दिल्ली और भुवनेश्वर को छोड़कर देश के ज्यादातर हिस्सों में खुदरा चीनी 10 रुपये प्रति किलोग्राम तक महंगी हो गई है। जबकि सरकार ने दावा किया था कि हते दस में कीमत पर काबू पा लिया जाएगा। खुदरा बाजार में चीनी की कीमत 50 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंचने के मद्देनजर सरकार ने 13 जनवरी को कुछ पहल किए थे। इसके तहत चीनी की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया गया और इसके लिए आयातित कच्ची चीनी को देश में कहीं भी साफ करने की अनुमति दी गई। साथ ही साफ चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अवधि को दिसंबर के अंत तक के लिए बढ़ा दिया गया। पहले यह अवधि 31 मार्च कों समाप्त हो रही थी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सरकार की घोषणा के बाद इसका थोक कीमतों पर मामूली असर हुआ। इस वजह से दिल्ली और भुवनेश्वर में जहां खुदरा कीमत में 2.3 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई वहीं मुंबई में एक रुपये की कमी हुई। दिल्ली, भुवनेश्वर और मुंबई में चीनी के खुदरा भाव घटकर क्रमशः 44 रुपये, 42 रुपये और 40 रुपये प्रति किलो रह गई। मगर तस्वीर का दूसरा पहलू कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। इन शहरों को छोड़ कर देश के ज्यादातर शहरों में इसके भाव ने सरकार के दावों को धता बताते हुए तेजी की राह पकड़ ली। यहां इन दस दिनों के भीतर कीमत में 10 रुपये प्रति किलो तक की वृद्धि हो गई। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश के दो और प्रमुख महानगर कोलकाता और चेन्नई में पिछले 10 दिनों में चीनी की खुदरा कीमतों में 7.8 रुपये प्रति किलोग्राम तक की तेजी आ गई। यह बढ़कर क्रमशः 45 रुपये और 42 रुपये प्रति किलो हो गई है। इसी तरह आईजोल में इसमें 10 रुपये की भारी तेजी दर्ज की गई और यह 35 रुपये पर बिकने लगी है। जबकि अहमदाबाद में कीमत चार रुपये बढ़कर 44 रुपये हो चुकी है। वहीं पटना और बेंगलुरु में इस दौरान 1से 2 रुपये की तेजी आई और यह क्रमशः 42 रुपये और 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। कीमतें घटाने के लिए किए गए सरकारी उपायों के प्रभावों के बारे में पिछले हते खाद्य एवं कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा था कि थोक बाजार में कीमतों में कुछ कमी आई है। खुदरा बाजारों में इसका असर 10 से 15 दिनों बाद दिखाई देने लगेगा। मगर चीनी की चाल उनके हर दावों को खोखला साबित करने में तुला हुआ है। ■

गणतंत्र के छह दशक : सच के आइने में भारत और भारतीय

&çHkkr >k

jk ष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस सदैव की तरह आ गया। प्रत्येक भारतीय की इच्छा यही होती है कि हमारा गणतंत्र अमर रहे। गणतंत्र का आकलन सदैव होते रहना चाहिये। आकलन में न आनाकानी होनी चाहिये न बेईमानी। आकलन यथार्थ की धरातल पर न हो तो हमें प्रगति का अनुमान नहीं लगेगा। हम कहां खड़े हैं, हमें कहां तक जाना है और जाने के लिये कहां और कैसे प्रयास करने हैं, इसकी जानकारी भी होनी चाहिये। देश को जानने का अधिकार प्रत्येक भारतीय को है। देश सिर्फ उनका नहीं जो सांसद या विधायक हैं। देश उनका भी नहीं है जो राजनीति में काम करते हैं। देश उन सभी का है, जो अपने को भारतीय कहते हैं। हमें गणतंत्र का ऊपरी हिस्सा तो दिखाया जाता है पर हमें नीचे का हिस्सा नहीं दिखाया जाता। हम देखने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहते। क्योंकि हमने भी देश उन्हीं का मान लिया है, जो देश चलाते हैं। हम अधिकारों की तो सदैव बात करते हैं पर कर्तव्यों के प्रति सदैव उदासीन रहते हैं। स्थितियां बदलनी है तो हमें देश की वर्तमान हालात पर नजर दौड़ानी होगी। सच्चाई से कब तक भागेंगे।

कृषि प्रधान देश की हालत कैसी है

आजादी के बाद से हम, अक्सर ही नहीं, हमेशा कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी आर्थिक आधार की जड़ कृषि है। बावजूद इसके हम कृषि क्षेत्र में आज कहां खड़े हैं? वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति कृषि जोत उपलब्धता 0.46 हेक्टेयर थी, जो 1992–93 में घटकर 0.19 हो गई। यह वर्तमान में 0.16 हेक्टेयर रह गई। वर्ष 1952–53 में 70 प्रतिशत जनसंख्या केवल 102.09 मिलियन हेक्टेयर कृषि पर आश्रित थी तथा उस समय कुल सिंचित क्षेत्र 18.1 प्रतिशत उत्पाद 59.2 मिलियन टन, उत्पादकता 580 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। यह वर्तमान में 122.4 मिलियन हेक्टेयर पर 45: सिंचित क्षेत्र के साथ कुल उत्पादन 230.3 मिलियन टन उत्पादकता 1854 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा कृषि आधारित उद्योगों में व्यस्त जनसंख्या 56 प्रतिशत है।

भुखमरी और कुपोषण से जूझता भारत

जून 2009 में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुये राष्ट्रपति महोदया ने कहा सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नामक एक नया कानून लायेगी। लेकिन अभी तक इस नियम की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। हमारे देश में 53 प्रतिशत आबादी जिसमें 20 प्रतिशत पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखते हैं, भुखमरी और कुपोषण के शिकार हैं। ताजा सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण भारत के डेढ़ करोड़ बच्चे कुपोषित होने के कगार पर हैं। विश्व की 27 प्रतिशत कुपोषित आबादी भारत में है। भारत में लगभग 2.8 प्रतिशत यानि बीस लाख बच्चे प्रति वर्ष मर जाते हैं, क्योंकि उनके जिन्दा रहने के लिये स्वच्छ जल नहीं मिल पाता।

स्थिति कितनी भयावह है और लोग कितने लापरवाह हैं इसका अंदाज तो इसी से लगाया जा सकता है कि देश में 58 हजार करोड़ का खाद्यान भण्डारण आधुनिक तकनीक के अभाव में नष्ट हो जाता है। क्या हम इसे बचाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा सकते? यह कैसी विडम्बना है कि कृषि आधारित व्यवस्था वाले देश की भुखमरी और कुपोषण में विश्व में 119 देशों में 94वां स्थान है। कहां जाना था और कहां जा रहे हैं?

बढ़ती गरीबी पर एक नजर

वास्तव में गरीबी और विषमता घटने के बजाय बढ़ गई है। आर्थिक विकास जितना बढ़ रहा है, उतनी ही गरीबी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष सुरेश तेन्दुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 37.2 प्रतिशत लोग बहुत गरीब हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2004–05 में किये गये 27.5 प्रतिशत के आकलन से करीब 10 फीसदी अधिक है। पिछले 11 वर्षों में अतिरिक्त 11 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं।

तेन्दुलकर समिति ने आगे बताया कि 41.8 प्रतिशत आबादी यानि 45 करोड़ लोग प्रति माह प्रति व्यक्ति 447 रुपये पर गुजारा कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे अपनी रोजमर्रा की जरुरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर हमें भारत की

खुशहाली के लिये और कितने गणतंत्र दिवस की बाट जोहनी होगी?

गणतंत्र के छह दशक बाद भी ग्रामीण व शहरी भारत में भारी विषमता

गांवों का विकास नहीं हो रहा। इस बात की गवाही सरकारी आंकड़े ही दे रहे हैं। शहरों में 77.70 फीसदी लोग पक्के मकान में रहते हैं, वहीं ग्रामीण भारत के महज 29.20 फीसदी लोगों के पास यह

सुविधा उपलब्ध है। शहरों के 81.38 फीसदी लोगों को पीने का पानी उपलब्ध है। वहीं गांवों के 55.34 फीसदी लोगों को ही पीने का पानी नसीब हो रहा है। शहरों के 75 फीसदी लोगों तक ही बिजली पहुंच पा रही है। वहीं गावों के सिर्फ 30 फीसदी लोग ही बिजली का लाभ उठा पा रहे हैं। देश के छह लाख गावों में साक्षरता दर 59 फीसदी है। जबकि देश के 5,161 शहरों के 80 फीसदी लोग साक्षर हैं। विषमता की खाई को पाटने का प्रयास तेजी से करना होगा। हम यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि आज भी देश की 72.22 फीसदी आबादी गावों में रहती है। अतः गांव के समग्र विकास के बिना हम दुनिया की दौड़ में भारत को आर्थिक रूप से मजबूत भी नहीं बना सकते।

विदेशी कर्ज का बोझ २३०.८० अरब डॉलर

हम चाहे जितनी डींग मार लें, आज भी हमारा भारत कर्ज में डूबा हुआ है। भारत पर विदेशी कर्ज का बोझ 31 दिसम्बर 2008 तक बढ़कर 230.80 अरब डालर के स्तर पर पहुंच गया जो समीक्षाधीन अवधि में 254.6 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भण्डार के मुकाबले मामूली रूप से कम है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) 4.6 अरब डॉलर बढ़कर 66. 16 अरब डॉलर पहुंच गई और सितम्बर 2008 के अंत तक कुल कर्ज में ईसीबी की हिस्सेदारी 27.4 फीसदी से बढ़कर 28.7 फीसदी पर पहुंच गई। हमारा ध्यान इन कर्जों पर क्यों नहीं जाता? हम स्विस बैंक में जमा राशि को लाने की व्यवस्था क्यों नहीं करते? हम अपने को कर्ज मुक्त करने की दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ा पाते? इन सवालों का जवाब देश चाहता है। देश इन विषयों पर सरकार से कारगर कदम की अपेक्षा रखता है।

२०२५ तक भारत की आबादी १.५ अरब हो जाएगी

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ने अनुमान व्यक्त किया है कि वर्ष 2025 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 1.5 अरब हो जाएगी। आयोग ने यह भी अनुमान लगाया है कि वर्ष 2025 तक आधी आबादी शहरों में रहने लगेगी। इस जनसंख्या को देखते हुये एक सेमीनार में 'समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन एक गंभीर' चुनौती पर बोलते हुये विशेषज्ञों ने कहा कि भारतीय शहरों में अगर कोई आपदा आये तो उसका नागरिकों पर गहरा असर पड़ेगा। हमारे लिये यह बहुत ही चिंता का विषय है। पर हम ऐसे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर कभी कोई विचार नहीं करते। आखिर कब तक हम नहीं करेंगे?

भारत एशिया का चौथा सबसे भ्रष्ट देश

विश्व में भ्रष्ट देशों में हमारी 85वां और एशिया में चौथा स्थान है। साल की शुरुआत से पहले ही देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सबसे बड़ी कम्पनी सत्यम् में हुये सात हजार करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया। इस दौरान संचार मंत्रालय का स्पेक्ट्रम, झारखण्ड़ के पूर्व राज्यपाल श्री सिब्ते रजी तथा एक पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधुकोड़ा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री के बेटे स्वीटी तथा हाल के दिनों में संसद में गूंजी जस्टिस दिनाकरण एवं सैन्य अधिकारियों के भूमि घोटालों ने भी भारत की साख को गहरा धक्का पहुंचाया है।

निराशाजनक शिक्षा व्यवस्था

एक तरफ सरकार लगातार यह दावा करती है कि प्राथमिक कक्षाओं में 90.95 फीसदी दाखिले हो रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ रही है। बच्चों और किशोरों की संख्या भी देश में लगातार बढ़ रही है। इस आधार पर भारत दुनिया में प्रथम पंक्ति के युवा राष्ट्रों में से एक बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके उलट आज हकीकत यह है कि युवाओं का एक तिहाई हिस्सा निरक्षर है अथवा

प्राथमिक स्तर की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पा रहा है। विडम्बना यह है कि जिस युवा भारत की तस्वीर पेश की जा रही है वह सूचना तकनीक कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट आदि की शहरी दुनिया में जीने वाले युवाओं की तस्वीर है। भारत के गांवों तथा शहरों की झोंपड़ पट्टियों में रहने वाले 70–80 फीसदी बच्चों, किशोरों और युवाओं से इसका कोई वास्ता नहीं है। इस असली युवा भारत के निर्माण के बगैर आखिर किस भारत निर्माण की बात हो रही है?

हमारे देश में लगभग 40 फीसदी बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के पहले स्कूल छोड़ने को मजबूर हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। यानि 100 बच्चों में से 60 बच्चे माध्यमिक कक्षाओं में जा पाते हैं। इन 60 में से 50 प्रतिशत बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सिर्फ 30 प्रतिशत बच्चे ही सेकेण्डरी शिक्षा पूरी कर पाते हैं। आगे देखेंगे तो इन 30: सेकेण्डरी पास बच्चों में 15 फीसदी बच्चे मात्र महाविद्यालयों में दाखिला लेते हैं। कुल मिला कर अगर देखें तो 100 बच्चे प्राथमिक कक्षाओं में दाखिला लेते हैं उनमें से 10–12 बच्चे कॉलेज पहुंच पाते हैं।

उच्च शिक्षा की हालत भी दयनीय

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये 4.50 लाख में से भी अधिक भारतीय छात्र प्रतिवर्ष विदेश जाते हैं और वे छात्र विदेशों में लगभग 48 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च करते हैं। भारतीय उद्योग संगठन एसोचैम की भी एक रिपोर्ट आयी है, उसके अनुसार अमेरिका, इंग्लैण्ड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर आदि देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये भारत से प्रतिवर्ष साढ़े चार लाख से अधिक बच्चे जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इस पलायन की सबसे बड़ी वजह है पर्याप्त संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा संस्थानों का अभाव। 'शिक्षा' के इस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार को एक जबर्दस्त रोडमैप बनाना होगा। अन्यथा भारतीय छात्र नस्ली हमले के शिकार भी होते रहेंगे और हमारी पूंजी से दूसरे देश मजबूत होते रहेंगे।

चिकित्सा के क्षेत्र में स्थिति नाजुक

अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आर्थिक समीक्षा 2008–09 के मुताबिक 2001 की जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार 20,855 उपकेन्द्रों 4833 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 2525 समुदाय स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। इसके अतिरिक्त विद्यमान स्वास्थ्य अवसंरचना का लगभग 34 प्रतिशत किराये के भवनों में है। इसी तरह जो स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं, उनमें डॉक्टरों एवं नर्सों की भारी कमी है। हालत इतनी नाजुक है कि देश के सैंकड़ों जिला चिकित्सालय बिना चिकित्सकों, विशेषज्ञों एवं नर्सों के चल रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में प्रतिदिन एक हजार लोग रोग से मरते हों, वहां सरकार सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक प्रतिशत ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करती है। जबकि पड़ोसी देश चीन अपने सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करता है।

आवास की विकट समस्या

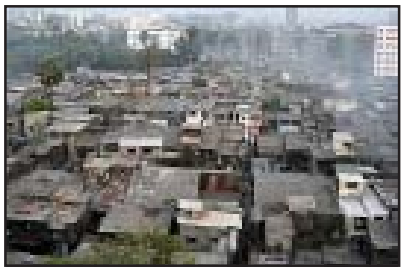

राष्ट्रीय आवास संगठन ने एक आंकड़ा जारी कर बताया है कि करीब ढाई करोड़ शहरियों यानि 37 फीसदी शहरी आबादी के पास अपना मकान नहीं है। नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 32 फीसदी भारतीय शहरियों को रहने के लिए अमेरीकी जेलों में कैदियों को मिलने वाले स्पेस के बराबर या उससे भी कम जगह मिल पाता है।

गांवों में 39 फीसदी लोगों के घर प्रतिव्यक्ति 65 वर्ग फीट की जगह मुहैया कराते हैं। पर बीते 50 वर्षों में शहर और गांव दोनों ही जगहों पर लोगों की जिंदगी तंग जगह पर सिमटने लगी है। आज 55 फीसदी शहरियों और 56 फीसदी ग्रामीणों के प्रति व्यक्ति बमुश्किल दस गुणा दस की जगह में जिंदगी बसर करनी पड़ती है। आप सुनकर हैरान होंगे कि यूएनहेबिटैट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 17 करोड़ लोग झुग्गियों में रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि वहां का जीवन तो शायद अमेरीकी जेलों से भी कई गुणा बदतर होता है।

अपार संभावनाओं से भरा भारत किन कारणों से अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर है जैसे विषयों पर प्रत्येक भारतीय को विचार करना होगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो वह सपना पूरा होने में कोई संदेह नहीं जब हम सभी एक स्वर से कहें ''मेरा भारत महान।''

'गणतंत्र दिवस' राष्ट्रीय पर्व है। हमने संविधान लागू किया था। हमने कहा था कि आम आदमी की जिंदगी के प्रति शासन जवाबदेह होगा। हमने प्रयास किया है कि सरकार के सामने रोटी–कपड़ा, मकान एवं देश की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सच्चाई सामने आएं। अपार संभावनाओं से भरा भारत किन कारणों से अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर है जैसे विषयों पर प्रत्येक भारतीय को विचार करना होगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो वह सपना पूरा होने में कोई संदेह नहीं जब हम सभी एक स्वर से कहें ''मेरा भारत महान।'' ■

लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व सांसद हैं

नए दशक की नीरस शुरुआत

fdसी समस्या पर रह–रहकर चर्चा होते रहने के बावजूद यदि उसका समाधान नहीं होता तो फिर वह अनसुलझी तो रहती ही है, उस पर होने वाली चर्चा भी नीरस और अंततः महत्वहीन हो जाती है। आज महंगाई और उस पर होने वाली चर्चा की कुछ ऐसी ही स्थिति है।

जो लोग अभी भी यह मानते हैं कि बढ़ती महंगाई के लिए मनमोहन सरकार का कोई दोष नहीं और यह तो परिस्थितियों मात्र की देन है उन्हें या तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों को कोसना चाहिए या फिर इस प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि मई 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को फिर से सत्ता में लाने की गलती तो नहीं की, ऐसा इसलिए, क्योंकि संप्रग सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में पहले कार्यकाल से भी बुरा प्रदर्शन कर रही है। इस पर गौर किया जाना चाहिए कि ऐसा तब है जब वाम दलों जैसा कोई घटक उसे परेशान करने की स्थिति में नहीं है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मई 2009 में आम चुनाव के समय विपक्ष नाकारा था और उसने सत्तापक्ष की खामियों को उजागर करने में भी नाकारापन दिखाया, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि सत्तापक्ष यानी मनमोहन सरकार सत्ता में वापसी के लिए आवश्यक योग्यताओं से लैस थी। पिछली बार तो संप्रग सरकार के पास कहने के लिए यह बहाना था कि उसकी असफलताओं के लिए वाम दल जिम्मेदार हैं, लेकिन इस बार तो उसके पास कोई बहाना नहीं। यह भी ध्यान रहे कि इस सरकार को बहाने बनाने की जरूरत अभी से पड़ने लगी है।

महंगाई के संदर्भ में ताजा बहाना यह है कि इसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। इस पर सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि शरद पवार के इस दावे में कोई दम नहीं कि अगले कुछ दिनों में आवश्यक वस्तुओं के दाम गिरेंगे। यदि किसी अप्रत्याशित घटनाक्रम के तहत आटा–दाल, चीनी–चावल के दाम कम भी हो जाएं तो भी महंगाई से निजात मिलने वाली नहीं, क्योंकि पिछले डेढ़–दो वर्षों में दैनिक आवश्यकता की सभी वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। इस पर भी नाउम्मीद रहने में ही समझदारी है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह महंगाई को लेकर मुख्यमंत्रियों का जो सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं उससे आम जनता को कुछ हासिल होगा, क्योंकि राज्य सरकारें पहले से ही केंद्र के इस आक्षेप से कुपित हैं कि महंगाई बढ़ने के लिए वे जिम्मेदार हैं।

> ***जो लोग अभी भी यह मानते हैं कि बढ़ती महंगाई के लिए मनमोहन सरकार का कोई दोष नह} और यह तो परिस्थितियों मात्र की देन है उन्हें या तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों को कोसना चाहिए या फिर इस श्कृन पर विचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि मई 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त श्गतिशील गठबंफ्रान को फिर से सत्ता में लाने की गलती तो नह} की।***

केंद्र सरकार के इस आक्षेप का सीधा मतलब यह भी है कि उसकी बात कांग्रेस शासित राज्य सरकारें भी नहीं सुन रही हैं। यदि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में चीनी–चावल, आटा–दाल उत्तार प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब आदि राज्यों के मुकाबले सस्ता नहीं है तो इसके दो ही अर्थ हो सकते हैं। एक यह कि केंद्र सरकार झूठ का सहारा ले रही है और दूसरा यह कि कांग्रेसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निर्देशों को ताक पर रख रहे हैं।

यदि केंद्र की इस दलील में दम होता कि महंगाई पर राज्य सरकारें सचेत नहीं तो प्रधानमंत्री की नाक के नीचे यानी दिल्ली में पीली मटर दाल की खूबियों के गुण नहीं गाए जा रहे होते। यह आम जनता से किया जाने वाला एक तरह का छल है कि उससे यह कहा जा रहा है कि जागरूक ग्राहकों, पीली मटर की दाल खाने में समझदारी है। इस सरकार से पूछा जाना चाहिए कि यदि अरहर दाल का विकल्प मटर की दाल है तो चीनी का विकल्प क्या है? क्षोभजनक यह नहीं है कि पिछले दो वर्षों से महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि यह है कि उसे थामने के लिए प्रयास तो दूर रहे, उसकी चिंता भी नहीं की जा रही।

यदि कोई यह सोच रहा है कि संप्रग सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में कृषि उपज बढ़ाने और किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ करेगी तो यह दिवास्वप्न देखने जैसा है।

आखिर जो सरकार कृषि उपज की घटत–बढ़त का अनुमान लगाने तक की जरूरत भी नहीं समझ रही वह कृषि–किसानों की चिंता क्यों करेगी, वैसे भी उसकी चिंता का एकमात्र विषय यह है कि उद्योग जगत को राहत पैकेज देना जारी रखा जाए या नहीं? इसमें दो राय नहीं कि मनमोहन सरकार के समक्ष कहीं कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है, लेकिन इसमें भी संदेह नहीं है कि यह सरकार साहसिक फैसले लेने और लीक

से हटकर चलने में समर्थ नहीं। किसी समस्या के गंभीर होने के बाद उसके अस्तित्व से अवगत होने की प्रतीति कराने वाली केंद्रीय सत्ता हर संकट का समाधान समितियों के माध्यम से करने में महारत हासिल कर चुकी है। यह एक ऐसी सरकार है जो आग लगने पर कुआं खोदने का उपक्रम तो करती है, लेकिन इसकी परवाह नहीं करती कि उससे पानी भी निकले। मनमोहन सिंह ने पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर विक्टर ह्यूंगो की इस चर्चित उक्ति का उल्लेख किया था कि जिस विचार के अमल का समय आ गया हो उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन न तो उनकी सरकार के पहले कार्यकाल में इसकी प्रतीति हुई कि भारत के भविष्य को संवारने का समय आ गया है और न दूसरे कार्यकाल में हो रही है।

मनमोहन सिंह सरकार के तौर–तरीके ऐसे हैं कि यदि वह अगले दस–बीस साल तक सत्ता में बनी रहे तो भी देश के विकसित राष्ट्र बनने का सपना साकार नहीं हो सकता, जबकि देश–दुनिया के विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि भारत के भविष्य के लिहाज से मौजूदा दशक महत्वपूर्ण है। इस दशक की जैसी निराशाजनक शुरुआत हो रही है उसके लिए एक हद तक मनमोहन सरकार ही उत्तारदायी है।

सदाबहार समस्या महंगाई के साथ–साथ कश्मीर की घटनाएं, आस्ट्रेलिया का घटनाक्रम, तेलंगाना समस्याए रेल दुर्घटनाएं, पाकिस्तान, नेपाल, चीन के तेवर और न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित प्रश्न आदि मिलकर कोई खुशनुमा अहसास नहीं करा पा रहे हैं तो इसके लिए मौसम को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। ■

असाभार : दैनिक जागरणफ

संप्रग सरकार ने क्षेत्र की जनता से छल किया : सुषमा स्वराज

yksकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने कांग्रेस पर अलग तेलंगाना राज्य के गठन के मामले पर क्षेत्र की जनता से छल करने का आरोप लगाते हुए केन्द्र से पृथक राज्य बनाने के लिए संसद में

विधेयक पेश करने की मांग की। भाजपा द्वारा आयोजित तेलंगाना के समर्थकों के सम्मेलन में श्रीमती स्वराज ने कहा कि सरकार को संसद के अगले सत्र में तेलंगाना के गठन पर एक विधेयक पेश करना चाहिए। भाजपा इस विधेयक का समर्थन करेगी। सरकार द्वारा तेलंगाना मसले पर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की अगुवाई में समिति गठित करने के कथित विचार पर उन्होंने कहा कि यह इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि राजग सरकार झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ ही तेलंगाना राज्य का गठन कर दिया होता लेकिन तेलगू देशम पार्टी (जिसने राजग को बाहर से समर्थन दिया था) ने इस योजना का विरोध कर दिया था। इसी बीच पृथक तेलंगाना राज्य के लिए लड़ रहे पिछड़ी जातियों के नेताओं ने कहा है कि हम भूस्वामियों के अलग राज्य के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि ऐसे राज्य के लिए जिसमें सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सभी विचार–विमर्श और बातचीत खत्म हो चुकी है। अब और बातचीत स्वीकार्य नहीं है। सरकार को संसद के अगले सत्र में विधेयक पेश करना चाहिए। केन्द्र को तेलंगाना की मांग माननी ही होगी क्योंकि तेलंगाना में समाज के सभी वर्ग आपसी मतभेद भूलकर एकजुट हो गए हैं। अलग तेलंगाना राज्य के गठन के विचार का समय आ गया है। गत वर्ष नौ दिसंबर को जब केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की और कहा कि चंद्रशेखर राव भूख हड़ताल समाप्त कर देंगे उसके बाद हम तेलंगाना राज्य के निर्माण की ओर बढ़ेंगे। लोगों ने सोचा कि यह सोनिया गांधी के जन्मदिन का तोहफा है। लेकिन अब सरकार अपने कहे को ही मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने केंद्र की ओर संकेत कर पूछा, आप कितनी बार तेलंगाना की जनता को ठगेंगे? तेलंगाना की मांग को पहली बार 1969 में प्रदर्शन हुआ। 1972 पृथक तेलंगाना राज्य का आंदोलन विधिवत रूप से शुरू हुआ। लेकिन जनता को जवाब नहीं मिल पाया है। ■

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

एक और विभाजन

जस्टिस सगीर अहमद की सिफारिशों के विनाशकारी परिणाम

ân;ukjk;.k nhf{kr

tम्मू–कश्मीर कड़ाके की सर्दी में भी गरमा गया है। अलगाववादी राजनीतिक दल पहले से ही स्वायत्तता मांग रहे थे। 26 जून, 2000 को विधानसभा ने एक खतरनाक स्वायत्तता प्रस्ताव पारित किया था। 6 अप्रैल, 2006 को मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा था कि जम्मू–कश्मीर ने 1947 से अब तक अपनी सरकार नहीं देखी। फारूख अब्दुल्ला ने 9 अप्रैल, 2006 को कहा था कि भारत ने जम्मू–कश्मीरी अवाम को 58 वर्ष से धोखा दिया है। उन्होंने केंद्र के बजाय भारत को धोखेबाज कहा। नवंबर 2009 में महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि 1947 से अब तक बलपूर्वक हमसे आत्मसमर्पण ही कराया गया है। जम्मू–कश्मीर को अरबों रुपए की केंद्रीय सहायता मिलती है। अनुच्छेद 370 के अधीन राज्य को विशेष दर्जा है तो भी भारत से अलग मुल्क बनाने की तैयारी है। बावजूद इसके केंद्र–राज्य संबंधों पर प्रधानमंत्री द्वारा गठित कार्यदल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सगीर अहमद ने भी स्वायत्तता की अलगाववादी मांगों पर मोहर लगा दी है। सगीर अहमद ने अनुच्छेद 370 के अस्थाई दर्जे पर अंतिम फैसले की भी पैरवी की है। लेकिन जम्मू में बीती 10 जनवरी को हुई बैठक में कार्यदल के सदस्यों में से पैंथर्स पार्टी के विधायक हर्षदेव, डा. अजय, अश्विनी कुमार, शेख अब्दुल रहमान व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने रिपोर्ट को फर्जी और नेशनल कांफ्रेंस का एजेंडा बताया है। जेटली ने सवाल उठाया कि सितंबर 2006 के बाद कार्यदल की कोई बैठक नहीं हुई तो यह रिपोर्ट कहां से आ गई? प्रधानमंत्री जी क्षमा करें। आपके आयोग और समितियां अलगाववादी सिफारिशों के लिए ही कुख्यात हो रही हैं। सच्चर कमेटी की सिफारिशें अलगाववादी हैं। लिब्रहान आयोग की रपट फर्जीवाड़ा और राष्ट्रीयता पर हमला है।

रंगनाथ आयोग संविधान विरोधी मजहबी आरक्षण की सिफारिशें लाया है। न्यायमूर्ति सगीर अहमद जम्मू–कश्मीर को अलग देश बनाने जैसी सिफारिशें पेश कर चुके हैं। राष्ट्रीय जिज्ञासा यह है कि संविधानविद्–न्यायमूर्ति भी तुष्टीकरण के एजेंडे को क्यों बढ़ाते हैं? क्या वे ऐसी सिफारिशें स्वयं लिखते हैं या संप्रग का कोई विशेषज्ञ समूह राजनीतिक दृष्टि से रपट लिखता है और वे हस्ताक्षर करते हैं। सगीर अहमद लंबे अर्से से बीमार हैं। वे कार्यदल के साथ नहीं बैठ पाए। रिपोर्ट केंद्र को देनी थी, लेकिन जम्मू–कश्मीर सरकार को पहुंचा दी गई, इस रिपोर्ट में नेशनल कांफ्रेंस की मांगों की शब्दावली है। केंद्र और राज्य संबंधों पर पहले भी तमाम रिपोर्टें बनी हैं। बहुप्रतिष्ठित सरकारिया आयोग की संस्तुतियां देश को याद हैं। क्या इस रिपोर्ट को नेशनल कांफ्रेंस के राजनीतिक इस्तेमाल के लिए ही केंद्र ने तैयार करवाया है? इस विवादास्पद और अलगाववादी रिपोर्ट के आने और केंद्र द्वारा कश्मीर से लगभग 30 हजार सैनिक बल हटाने का समय लगभग एक है। क्या केंद्र ने स्थानीय सरकार और अलगाववादियों से कोई गुप्त समझौता किया है? क्या पाकिस्तान भी इस खेल में शामिल है। स्वायत्तता की ऐसी ही मांग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरी क्षेत्र से भी उठी है। हाल ही में पाक अधिकृत कश्मीर के प्रधानमंत्री फारूख हैदर ने भी इस्लामाबाद केंद्रित आजाद जम्मू–कश्मीर काउंसिल को असंवैधानिक बताया है। यह काउंसिल कथित आजाद जम्मू–कश्मीर के अंतरिम संविधान 1974 की धारा 21 के अधीन काम करती है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, छह अन्य सदस्य पाकिस्तानी संसद से व बाकी सदस्य स्थानीय होते हैं। दोनों तरफ से समान मांगों का एक साथ उठना मात्र संयोग नहीं हो सकता। केंद्र जम्मू–कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय विवाद मानने वाली अमेरिका जैसी ताकतों के प्रभाव में है। दोनों कश्मीरी क्षेत्रों को मिलाकर एक नया देश बनाने की गुपचुप तैयारी दिखाई पड़ रही है। ख्वाब यह है कि इस नए राज्य में भारत और पाकिस्तान की साझा मुद्रा भी चलेगी। लेकिन तब संसद द्वारा समूचे कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताने वाले सर्वसम्मत संकल्प का क्या होगा? जम्मू–कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह महाराजा हरी सिंह के विलय प्रस्ताव से ही भारत का अंग नहीं बना। इस्लामी हमलों के पहले भी यह भारत का अंग था। यहीं उत्तर वैदिक काल में देश के

श्प्राानमंत्री जी क्षमा करें। आपके आयोग और समितियां अलगाववादी सिफारिशों के लिए ही कुख्यात हो रही हैं। सच्चर कमेटी की सिफारिशें अलगाववादी हैं। लिब्रहान आयोग की रपट फजवाड़ा और राष्टौयता पर हमला है।

रंगनाथ आयोग संविप्राान विरोप्री मजहबी आरक्षण की सिफारिशें लाया है। न्यायमूर्ति सगीर अहमद जम्मू–कश्मीर को अलग देश बनाने जैसी सिफारिशें पेश कर चुके हैं। राष्टौय जिज्ञासा यह है कि संविप्राानविद्–न्यायमूर्ति भी तुष्टीकरण के एजेंडे को क्यों बढ़ाते हैं? क्या वे ऐसी सिफारिशें स्वयं लिखते हैं या संश्ग का कोई विशेषज्ञ समूह राजनीतिक दृष्टि से रपट लिखता है और वे हस्ताक्षर करते हैं।

कोने–कोने से आए छह दार्शनिकों ने पिप्पलाद ऋषि से सृष्टि रहस्यों पर तर्क किए थे। इन्हीं प्रश्नों प्रतिप्रश्नों का संग्रह विख्यात दर्शन ग्रंथ प्रश्नोपनिषद् है। अभिनव गुप्त का प्रत्यभिज्ञा दर्शन यहीं उभरा। जम्मू–कश्मीर भारतीय संस्कृति, संस्कृत और दर्शन की प्राचीन भूमि है। इसे अलग करने की कोई भी साजिश बर्दाश्त के बाहर होगी। भारत अब और टूटने को तैयार नहीं है। 1947 के रक्तपात और विभाजन के नतीजे यह राष्ट्र अभी भी नहीं भूला। इसका कोई भी भूभाग किसी राजनेता या राजनीतिक दल की जागीर नहीं है। स्वायत्तता और स्वतंत्र राष्ट्र में फर्क करना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने अस्थाई अनुच्छेद 370 जोड़कर ही महापाप किया था। सगीर अहमद ने इसी दुखती रग को फिर से छेड़ने की कोशिश की है। संविधान में प्रत्येक राज्य की स्वायत्तता है। ढेर सारे अधिकार हैं। जम्मू–कश्मीर भी एक राज्य है। इसे ज्यादा स्वायत्तता चाहिए तो दीगर राज्य भी ऐसी ही स्वायत्तता का दावा क्यों नहीं कर सकते? पूर्वोत्तर के राज्यों में आगजनी और बमबाजी है। वे भी तमाम तरह की स्वायत्तता मांगें रहे हैं। अब तक जम्मू–कश्मीर सहित ऐसे तनावग्रस्त राज्यों की मांगे स्थानीय गुटों, दलों द्वारा की जाती थीं, लेकिन इस बार केंद्रीय प्राधिकार भी इस खेल में शामिल है। कांग्रेस में इतिहासबोध और भविष्यदृष्टि का अभाव है। पं. नेहरू ने 1948 के कबाइली हमलावरों को खदेड़ती सेना को बीच में ही रोक दिया था। तबसे आज तक वही एलओसी है। वह मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ ले गए। शेख अब्दुल्ला इसे स्वतंत्र मुल्क बनाना चाहते थे। पं. नेहरू ने संसद में 26 जून, 1952 कहा था, आप यूपीए बिहार या गुजरात नहीं एक विशेष क्षेत्र पर विचार कर रहे हैं। ऐतिहासिक, भौगोलिक और सभी नजरिए से इस क्षेत्र की भिन्न स्थिति है। इसी सोच और समझौते से अनुच्छेद 370 आया था। शेख अब्दुल्ला इस राज्य के प्रधानमंत्री बने, अलग राष्ट्रीय ध्वज और अलग संविधान भी बना। डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान के विरोध में आंदोलन किया। वे शहीद हो गए। अमरनाथ भूमि विवाद को लेकर हुआ जबर्दस्त आंदोलन अभी ताजा है। क्या स्वायत्तता और आजादी पर्यायवाची हैं? जम्मू–कश्मीर विधानसभा (26 जून, 2000) का स्वायत्तता प्रस्ताव गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 के पहले दर्ज अस्थाई शब्द हटाइए और इसकी जगह विशेष लिखिए। अनुच्छेद 324. निर्वाचन आयोग के अधिकार इस राज्य में हटाइए। अनुच्छेद 355. केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश के अधिकार, 356. राज्य सरकार की बर्खास्तगी के साथ ही 357, 358 और 360 भी यहां लागू न हों। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता (अनुच्छेद 218, 220, 222 व 226) इस राज्य से समाप्त कीजिए। इसी तरह के ढेर सारे संवैधानिक उपबंधों के साथ ही संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की सर्वोपरिता (अनुच्छेद 254) से भी इस राज्य को मुक्त किए जाने की मांग स्वायत्तता है। सगीर अहमद की सिफारिशें इसी स्वायत्तता की पैरोकार हैं। प्रधानमंत्री जी कृपया बताइए कि संविधान आधारित स्वायत्तता व स्वतंत्र राष्ट्र में फर्क क्या है? वे स्वायत्तता के नाम पर आजाद मुल्क मांग रहे हैं और आप इसे स्वायत्तता बता रहे हैं। ■

जलेखक उ॰ सरकार के पूर्व मंत्री हैंफ

पंजाब

आतंकवाद : राष्ट्रीय एकता को खतरा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल के साथ एक सुर में कहा कि आतंकवाद राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन गया है। यह देश की एकता को खंडित कर रहा है। आतंकवादी पर्यटक के रूप में देश में घुसते हैं। सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या कर राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात करते हैं। देश के कई हिस्सों में सरकार का शासन नहीं चलता। दुश्मन देश राकेट दागता है और केन्द्र सरकार खामोश बनी रहती है। भाजपा एवं शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के दोनों वरिष्ठ नेता भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. बलदेव प्रकाश की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक रैली को संबोधित कर रहे थे।

पंजाब के अपने पहले दौरे में श्री गडकरी ने देश की राजनीति में मूल सुधारों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तीन वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ने की अपनी घोषणा को दोहराते हुए कहा राजनीति का मकसद सेवा–विकास होना चाहिए, मगर दुर्भाग्य से आज राजनीति में आने का मकसद विधायक व सांसद बनना हो गया है। हमें इस सोच को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत भय, भूख व आतंक से मुक्त हो, भाजपा ने इसकी परिकल्पना कर ली है। देश इंफामेशन टेक्नोलॉजी, बायो–टेक्नालॉजी के साथ–साथ इतिहास, संस्कृति, धरोहर व नैतिक मूल्यों पर पहरा देते हुए आगे बढ़े, इसके लिए निरंतर प्रयास जारी रखेंगे। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश को 55 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत है, परंतु केन्द्र सरकार के पास इसके लिए नीति नहीं है। उसकी आर्थिक नीतियां महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं।

शिअद के संरक्षक एवं मुख्यमंत्री बादल ने राज्य की स्थायी शांति को भंग करने वाली शक्तियों के विरूद्ध एकजुट होने के लिए प्रदेशवासियों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक शक्तियां राज्य को एक बार फिर आतंकवाद की आग में झोंकने का षड्यंत्र रच रही हैं। इनको कांग्रेस का साथ मिला हुआ है। बादल ने गडकरी से आग्रह किया कि वह महंगाई, बेरोजगारी व अशिक्षा के विरूद्ध पंजाब से आंदोलन शुरू करें। आंदोलन में शिअद पूरा साथ देगा। ■

नहीं रहे कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वरिष्ठ नेता व पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का 17 जनवरी को निधन हो गया। वो 95 साल के थे। ज्योति बसु का जन्म आठ जुलाई, 1914 को महानगर के हैरीसन रोड (अब महात्मा गांधी रोड) स्थित एक घर में हुआ था। सेंट ज़ेवियर्स में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद बसु ने आगे की पढ़ाई के लिए प्रेसीडेंसी कॉलेज में दाख़िला लिया। 1935 में वे वकालत पढ़ने ब्रिटेन गए। बसु वहां चार साल तक रहे और उनके मन में वामपंथी आंदोलन के बीज इंग्लैंड में रहने के दौरान ही पड़े।

1957 में ज्योति बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। राज्य

में साठ के दशक के उत्तरार्द्ध में नक्सल आंदोलन ने भी जोर पकड़ा। बसु उसी समय राज्य में बनी साझा सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन यह सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकी। उसके बाद राज्य में फिर कांग्रेस सत्ता में आई। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में हुए विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चा भारी बहुमत के साथ जीत कर सत्ता में आया। ज्योति बसु उसके पहले मुख्यमंत्री बने और तमाम रिकॉर्ड बनाते हुए 23 साल से भी लंबे अरसे तक इस पद पर बने रहे।

उन्होंने लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का एक अनूठा विश्व रिकार्ड बनाया। राज्य में भूमि सुधारों को लागू करने में बसु ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। वहीं दूसरी ओर बसु के कार्यकाल की आलोचना भी खूब हुई। उनके कार्यकाल में हजारों की तादाद में कल–कारखाने बंद हुए, लाखों मजदूर बेरोजगार हुए। पढ़े–लिखे बेरोजगारों की फौज भी लगातार बढ़ती रही। कभी पढ़ाई में अव्वल रहने वाला बंगाल लगातार फिसड्डी होता गया। शिक्षा के अलावा इस दौरान स्वास्थ्य सेवाएं भी बदहाल होती गईं। ■

शोक संदेश

अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री

श्री ज्योति बसु के नहीं रहने से राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया है। दिवंगत बसु एक कुशल प्रशासक और जुझारू राजनीतिक कार्यकर्ता और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल में न केवल सर्वाधिक समय तक शासन करनेवाले मुख्यमंत्री का रिकार्ड बनाया बल्कि अनेक दूरगामी कदम उठाये। वे अपने विचारों के प्रति अडिग और उसके लिये संघर्ष करनेवालों में से थे। वे अपने परिश्रम से मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे।

लालकृष्ण अडवाणी, चेयरमैन, भाजपा संसदीय दल

ज्योति बसु के न रहने से भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन को धक्का लगा है। ज्योति बसु एक बड़े दिग्गज और महान नेता थे। हमारी विचारधाराएं अलग रही हैं, लेकिन उनकी महानता को ध्यान में रखते हुए मैं उनकी बहुत इज्ज़त करता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ।

नितिन गडकरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

ज्योति बसु समकालीन भारत के शीर्ष नेताओं में थे। वह ऐसे नेता थे जो समाज के निचले तबके के प्रति समर्पित थे। वह विचारधारा और अपने आदर्शों के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। यह उनका कद व उनकी विश्वसनीयता ही थी जिसके चलते उन्होंने राजनीतिक जीवन में इतनी लंबी पारी खेली। वह वामपंथ के वास्तविक पुरोधा थे।■

'छोटे लोहिया' जनेश्वर मिश्र का निधन

छोटे लोहिया के नाम से सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद जनेश्वर मिश्र का 22जनवरी को निधन हो गया। 5 अगस्त 1933 को बलिया में जन्मे मिश्र की शिक्षा–दीक्षा बलिया और इलाहाबाद में हुई थी। श्री मिश्र 1969 में पहली बार लोकसभा में फूलपुर संसदीय सीट से पहुंचे थे। जनेश्वर मिश्र 1990–91के दौरान चंद्रशेखर की सरकार में रेल मंत्री रह चुके हैं। मिश्र की पहचान समाजवादी पार्टी के चेहरे के तौर पर रही है। मिश्र इलाहाबाद से तीन बार सांसद रहे हैं। जनेश्वर मिश्रा 70 के दशक से राजनीति में सक्रिय थे। जनता पार्टी की सरकार में पहली बार वे मंत्री बने। समाजवादी पार्टी की ओर से वे राज्य सभा के लिए तीसरी बार चुने गए थे। इलाहाबाद में शनिवार को जनेश्वर मिश्र का अंतिम संस्कार होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा सांसद जनेश्वर मिश्र के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। कहा कि उनके निधन से राष्ट्रीय राजनीति को जो क्षति पहुंची है। उसकी भरपाई काफी मुश्किल है। भाजपा, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री रमापति राम त्रिपाठी ने शोक संदेश में कहा कि वैचारिक असहमति के बावजूद जनेश्वर मिश्र सभी दलों में लोकप्रिय थे। ■

कब खुलेगा नेताजी की मौत का राज

fgek'k 'k[kj

b स मर्तबा भी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन हर साल की तरह ही मनाया जाएगा और रस्मी तौर पर उन्हें याद किया जाएगा, पर आजादी के बासठ साल से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद 23 जनवरी 1897 को जन्मे भारत के स्वतंत्रता आदोलन के इस नायक की मौत के बारे में सही जानकारी अब तक लोगों को नहीं मिल पाई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान आखिर कैसे गई?

यह एक ऐसा सवाल है, जो हर हिंदुस्तानी को सोचने पर मजबूर कर देता है। बीते दिनों सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारियों के बाद इस अनसुलझी पहेली के तार और ज्यादा उलझते नजर आ रहे हैं। पर सरकारी और गैर–सरकारी स्तर पर नेताजी की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। सरकारी महकमा कहता आया है कि 1945 में हुई विमान दुर्घटना में ही नेताजी की मौत हो गई। पर इस महान देशभक्त में रुचि रखने वालों और नेताजी पर अध्ययन करने वालों का दावा है कि नेताजी की जान विमान हादसे में नहीं गई थी। पर अहम सवाल यह है कि ये दावे तथ्यों और तर्को की कसौटी पर कितना खरे उतरते हैं?

18 अगस्त 1945 को कथित तौर पर ताईवान में एक विमान दुर्घटना हुई थी। भारत सरकार कहती रही है कि इस हादसे में मरने वालों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। अब तक यह कहा जाता रहा है कि महात्मा गाधी से बगावत करके जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन करके फिरंगियों के खिलाफ भारत की आजादी के लिए जंग छेड़ने वाले नेताजी की अस्थिया जापान के रेंकोजी टेंपल में रखी हुई हैं। नेताजी की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए बनी शाहनवाज कमेटी और खोसला कमीशन की रिपोर्ट भी इसी बात की पुष्टि करती है। पर मामले का दूसरा पहलू हैरत में डालने वाला है। अब यह कहा जा रहा है कि नेताजी की मौत उस विमान हादसे में नहीं हुई थी। अब इस पर भी विवाद पैदा हो गया है कि विमान दुर्घटना हुई भी थी या नहीं। उस कथित विमान हादसे पर सवालिया निशान खुद ताइवान सरकार लगा रही है। ताईवान सरकार ने कहा है कि 18 अगस्त 1945 को वहा कोई विमान हादसा नहीं हुआ था। ऐसा होता तो ताईवान के अखबारों में उस समय यह खबर जरूर छपी होती।

वर्ष 1999 में एनडीए सरकार ने नेताजी की मौत की तहकीकात के लिए जस्टीस एमके मुखर्जी की अध्यक्षता में मुखर्जी आयोग का गठन किया। मुखर्जी आयोग ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि नेताजी की मौत उस कथित विमान हादसे में नहीं हुई थी। अहम सवाल यह है कि आखिर किस रिपोर्ट को सही माना जाए। एनडीए के नेता कहते रहे हैं कि नए तथ्यों के अधार पर मुखर्जी आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि नेताजी की मौत उस विमान हादसे में नहीं हुई। पर सियासी वजहों से काग्रेस सरकार ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया।

इससे इतना तो साफ है कि एक महान देशभक्त की मौत पर भी अपने देश के नेता सियासत करने से बाज नहीं आए। सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर काग्रेस के राज में गठित कमेटी उसकी मर्जी के मुताबिक और एनडीए के राज में बनाई गई कमेटी उसकी विचारधारा के मुताबिक रिपोर्ट क्यों देती है? बड़ा सवाल यह है कि स्वतंत्रता की लड़ाई के एक महान नायक नेताजी के बारे में आजाद भारत के लोगों को सच्चाई का पता कब चल पाएगा? मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट आने के पहले भी नेताजी की मौत को लेकर खासा विवाद रहा है। कई लोग लंबे समय से यह दावा करते रहे हैं कि जापान के रेंकोजी मंदिर में रखी गई अस्थिया नेताजी की नहीं, बल्कि वह एक जापानी सैनिक की है, लेकिन सरकार इसे ही नेताजी की अस्थिया मानती रही है और जापान दौरे पर जाने वाले हिंदुस्तानी नेता भी इसी के आगे सिर झुकाते रहे हैं।

अब यह बात खुल गई है कि जापान के रेंकोजी मंदिर में 1945 से संभाल कर रखी जा रही अस्थिया नेताजी की नहीं हैं। मुखर्जी आयोग ने इस बात की पुष्टि तो की ही, साथ ही इस मसले पर 1965 में बनाई गई शाहनवाज जाच समिति में भी मतभेद रहा है। शाहनवाज समिति के तीसरे सदस्य नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ–साफ लिखा है कि इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर यह मान लिया जाए कि टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी अस्थिया नेताजी की हैं।

नेताजी को जिस कथित विमान हादसे का शिकार बताया जाता है, उसमें उनके साथ लेटिनेंट कर्नल हबीबुर्रहमान खान भी थे। उनसे इस बारे में कई बार पूछताछ की गई। उन्होंने बार–बार यही कहा कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में बुरी तरह जल गए थे और इसके बाद उनकी मौत अस्पताल में हो गईं थी। सुभाष चंद्र बोस से जुड़े विषयों पर काम करने वाली संस्था मिशन नेताजी के लोगों ने जब इस बारे में तथ्यों को खंगाला तो उन्हें इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले कि रहमान ने नेताजी के बारे में जो कहा वह सच नही था। 1946 में जब उन्हें अपने मित्र और नेताजी के सचिव मेजर ई भास्करन ने नेताजी की मौत के बारे में कुरेदा तो रहमान ने कहा

था कि उन्होंने नेताजी को वचन दे रखा, लिहाजा इस बारे में कुछ नहीं कह सकते।

सूचना के अधिकार के तहत जब जानकारी मांगी गई कि जापान के रेंकोजी मंदिर में रखी गई अस्थियों को भारत लाने के लिए सरकार क्या कर रही है? इस सवाल का जो जवाब मिला, उससे सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगता है। जवाब में कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को भारत लाने के संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। जब सरकार मानती है कि वे अस्थियां नेताजी की ही हैं तो सवाल यह उठता है कि आखिर उन्हें अब तक भारत क्यों नहीं लाया गया? एक सरकारी फाइल में तो उस समय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के सचिव रहे एमओ मथाई ने लिखा है कि भारत के विदेश मंत्री ने टोकियो के भारतीय उच्चायोग से नेताजी की अस्थियों और नेताजी के कुछ और सामानों के साथ उनके पास से मिले तकरीबन दौ सौ रुपये रिसिव किए थे। मालूम हो कि उस समय विदेश मंत्रालय भी जवाहर लाल नेहरू के पास था।

अहम सवाल यह है कि इन अस्थियों का क्या किया गया? क्या ये अस्थिया नेताजी के परिजनों के पास पहुंची? इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। यह बात भी सामने आई है कि रेंकोजी मंदिर के पुजारी ने 23 नवंबर 1953 को प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु को पत्र लिखकर बताया था कि 18 सितंबर 1945 से नेताजी की अस्थिया वहा रखी जा रही हैं तो उस समय नेताजी की अस्थियों को वापस लाने के लिए आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए? जाहिर है 1945 से लेकर अब तक नेताजी के मामले में सरकार का रवैया गैर–जिम्मेदराना रहा है। आखिर देश के एक महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी नेताजी के बारे में सच देश की जनता के सामने आ पाएगा? यह एक ऐसा सवाल है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। मौजूदा सरकार भी इस दिशा में कुछ करती नजर नहीं आ रही है।■

महंगाई के नाम पर यूपीए सरकार का महाघोटाला

भाजपा के राष्ट्रीय श्वक्ता एवं संसद सदस्य
श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि अपने सभी दायित्वों से पल्ला झाड़ते हुए श्री शरद पवार अब यह बेतुका और हास्यास्पद बयान दे रहे हैं कि देश के सभी जिलों में बरसात हो और महंगाई कम हो जाए, इसकी अगर कोई गारंटी लेता है तो मैं इस्तीफा दे सकता हूं। यह वक्तव्य पूर्णतः गैर–जिम्मेदाराना है और यूपीए सरकार के उस झूठे दावे की कलाई खोलता है, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर दोबारा यूपीए की सरकार बनती है तो 100 दिनों में हम महंगाई को कम कर देंगे। आम आदमी के नाम पर बनी सरकार सटोरियों और जमाखोरों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार बन गई है। उक्त वक्तव्य महंगाई से पीड़ित आम आदमी की पीड़ा के साथ क्रूर मजाक है। यह सरकार घोटालों की सरकार है। इस संबंध में निम्नांकित तथ्य सच्चाई को सामने रखते हैं :

गेंहू घोटाला

एनडीए की सरकार के समय में देश में भयंकर अकाल पड़ा था। उसके बावजूद गेंहू 9 रूपए प्रतिकिलो की दर से उपलब्ध था। शरद पवार 22 मई, 2004 से देश के कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री है और 2007 से आज तक लगातार महंगाई बढ़ रही है। एक तरफ शरद पवार द्वारा अकाल का रोना रोया जा रहा है दूसरी तरफ यूपीए सरकार संसद में और संसद के बाहर यह दावा कर रही है कि यूपीए सरकार के समय में अन्य का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2007, 2008 और 2009 में 2348 लाख टन गेंहू का उत्पादन हुआ। सरकार ने दावा किया कि एफसीआई के गोदाम गेहूं से भरे हुए हैं। इसके बावजूद भी सरकार ने 2007 में 19 रूपए प्रतिकिलो की दर से घटिया गेहूं आयात किया और आज ग्राहक को वही गेंहू 24 रूपए प्रति किलो की दर से मिल रहा है। यानी पिछले छह वर्षों में 300 प्रतिशत महंगा, यह घोटाला नहीं तो और क्या है ?

चावल घोटाला

एनडीए सरकार के समय में देश में चावल 10 रूपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध था। आज वही चावल 48 रूपए प्रति किलो की दर से मिल रहा है। सरकारी आंकड़े कहते है कि 2009 में 991 लाख टन चावल की रिकार्ड पैदावार हुई और किसान को 10 रूपए प्रति किलो की दर से भुगतान किया गया। यानी 500 प्रतिशत महंगा, यह घोटाला नहीं तो और क्या है ?

चीनी घोटाला

एनडीए की सरकार के समय में चीनी 14 रूपए प्रतिकिलो की दर से उपलब्ध थी। वर्तमान सरकार ने चीनी की बहुतायत बताते हुए वर्ष 2008 में 12.50 रूपए किलो की दर से चीनी का निर्यात किया और निर्यातक को 1.44 रूपए प्रतिकिलो सब्सिडी दी गई। और 6 महीनों के अंदर अंतराल में अचानक सरकार को चीनी की किल्लत महसूस हुई, और वर्ष 2009 में वही चीनी 30 रूपए प्रतिकिलो की दर से आयात की गई। और आज वही चीनी ग्राहक को 45 रूपए प्रतिकिलो की दर से परोसी जा रही है। यानी लगभग 250 प्रतिशत महंगी, यह घोटाला नहीं तो और क्या है ?

दाल घोटाला

एनडीए की सरकार के समय में चना दाल 25 रूपए प्रतिकिलो की दर से उपलब्ध थी। आज वही दाल 56 रूपए प्रतिकिलो की दर से बेची जा रही है।

एनडीए की सरकार के समय में मूंग दाल 24 रूपए प्रतिकिलो की दर से उपलब्ध थी। आज वही दाल 100 रूपए प्रतिकिलो की दर से परोसी जा रही है।

यानी 400 प्रतिशत महंगी, यह घोटाला नहीं तो और क्या है ?

भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से पूछना चाहती है कि क्या ये घोटाले आपकी सहमति से हुए ? अगर नहीं, तो अविलंब खाद्य आपूर्ति एवं कृषि मंत्री श्री शरद पवार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और इन सभी घोटालों की सीबीआई जांच की जाए और गरीब किसान को लूटने वाले लुटेरों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।■

'लोकमाता' विजया राजे सिंधिया

jkजमाता विजयाराजे सिंधिया को लोग राजमाता कहने में कतई संकोच नहीं करते थे। किसी भी नागरिक या भाजपा के कार्यकर्ता को उन्हें राजमाता कहने में असहजता नहीं होती थी क्योंकि वह व्यक्तित्व की बहुत सहज थीं और उनकी सहजता ही उन्हें लोकमाता बनने में सहायक सिद्ध हुई। राजशाही से लोकशाही तक की यात्रा पर दृष्टि डालें तो देखने में आता है वह राजमाता होते हुए भी हर दृष्टि से लोकतांत्रिक थीं। वे नैसर्गिक रूप से सामाजिक थीं और जनता के प्रति उनमें सहानुभति रहती थी। वह समझौतावादी नहीं थीं। वे जबसे विचारधारा से जुड़ीं तबसे उन्होंने प्रतिकूल धारा में भी विचारधारा नहीं छोड़ी। महल की महारानी को आपातकाल में जब इंदिराजी के निर्देश पर उन्हें सलाखों के पीछे किया गया तो राजमाता उन सलाखों से भी मजबूत दृढ़ प्रतिज्ञ बनकर निकलीं और निखरीं। वे अध्यात्म के सान्निध्य में रहकर राजनीति करती थीं। राज करना उन्हें विरासत में मिला था पर वो राज शान के लिए, गरीबों की जान बचाने के लिए करती थीं। भारत के इतिहास में जनता के लिए सड़कों पर पार्टी का झंडा उठाकर संघर्ष करने में वे सदैव अग्रणी रहीं।

उनके नेतृत्व में अनेकों बार मध्यप्रदेश में सरकार बनी। केन्द्र में भी सरकार बनी। पर वे कभी सरकारी पद से नहीं बंधीं। राजमाता ने सदैव लालबत्ती अस्वीकार की। उनका कहना था कि मैं लालबत्ती नहीं जनशक्ति में विश्वास करती हूं। विचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण तो यही है वो अपने कोख से जन्मे पुत्र से भी दो–दो हाथ करने में नहीं चूकीं।

उन्हें गहरा सदमा लगा था जब उनके पुत्र माधवराव सिंधिया ने आपातकाल का समर्थन किया था और संजय गांधी से बातचीत की थी। भारत में विरले राजा–महाराजा हुए हैं जिन्होंने अपनी सेवा, शिक्षा संस्थानों, आध्यात्मिक केन्द्रों को दान में दे दिया। उन्हें कभी संपत्ति से मोह नहीं रहा। वो समर्थ भारत बनाने की हामी थी। राजमाता जी कहा करती थी, 'मैं राजनीति में स्व. पं. दीनदयालजी उपाध्याय का वह सपना पूरा करने आयी हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सेवा समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए कारगर होगी तब हम समझेंगे कि भारत समर्थ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजनीति को उन्होंने कभी मौज–मस्ती का अखाड़ा नहीं माना। श्रीरामजन्मभूमि का मसला हो या महंगाई के विरूद्ध संघर्ष हो या सत्ता परिवर्तन के लिए सतत् प्रयास करने की बात आयी हो वह कभी पीछे नहीं रहीं। वो कष्टों के बीच और निखरीं। संगठन ने आदेश दिया तो रायबरेली में श्रीमती इंदिराजी को चुनौती दी। वो जानती थी कि वो चुनाव नहीं जीतेंगी पर 'संगठन का आदेश सर्वोपरि' की मान्यता रखने वाली राजमाता ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर से कहा– मैं लडूंगी और लड़ीं।

आजादी के बाद भारतीय नारियों का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उस इतिहास का सबसे पहला पन्ना राजमाता जी को समर्पित करेगा। वह वात्सल्यता की प्रतीक थीं। अपने अनथक प्रवास से उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा को नयी पहचान दी। केरल से कन्याकुमारी तक भारत को एक नहीं अनेकों बार उन्होंने अपने प्रवास से नापा। रा.स्व.संघ के प्रति और हिन्दुत्व विचारधारा के प्रति अगाध श्रद्धा एक नहीं अनेकों बार देखने को मिली।

सन् 1967 को मध्यप्रदेश में बनी संविद सरकार की भी चर्चा होती है तो लोगों के सामने पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र के खिलाफ राजमाता विजया राजे सिंधिया द्वारा छेड़ा गया संघर्ष सहज सामने आ जाता है। देश के पहले राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद से लेकर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनकी जयविलास स्थित महल में आ चुके थे। उनके सबसे निजी संबंध थे। मार्शल टीटो से लेकर अनेकों राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष तक उन्हें मिलने आते थे पर उन्हें कभी इन बातों का मान नहीं रहा। वे सदैव सर्वसुलभ रहा करती थीं। उन्होंने अपने महल को जनता का मंदिर बनाने का सपना साकार किया। वे मप्र में जितनी बार भी चुनाव लड़ीं सबमें विजयी रहीं। उनके जीवन पर जनसंघ के संस्थापकों कुशाभाऊ ठाकरे का बहुत असर था। यहां तक कि उन्होंने अपनी विरासत में यह लिखा कि कुशाभाऊ मेरे पुत्र समान हैं और इसमें

.....शेष पृष्ठ 30 पर

वे जबसे विचारफ्रारा से जुड़ीं तबसे उन्होंने प्रतिकूल फ्रारा में भी विचारफ्रारा नहीं छोड़ी। महल की महारानी आपातकाल में जब इंदिराजी के निर्देश पर उन्हें सलाखों के पीछे किया गया तो राजमाता उन सलाखों से भी मजबूत दृढ़ प्रतिज्ञ बनकर निकलीं और निखरीं। वे अफ्रयात्म के सान्निफ्रय में रहकर राजनीति करती थीं।

'आईटी में बेंगलुरु के बाद होगा बिहार'

अभी तक भारत में विकास के पायदान पर पिछड़े गिने जाने वाले बिहार ने 2008.09 में 11.03 फीसदी की ग्रोथरेट के साथ सक्सेस की नई इबारत लिखी है। बिहार से जो लोग नौकरियों की तलाश में बाहर गए थे, वे घर लौटने लगे हैं। आईटी सेक्टर में भी उसी तरह के मौके हैं, जैसा कि देश में अन्य जगहों पर। गौरवशाली बिहार की यह नींव रखी है राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने।

ऐसे कायम रहेगी ग्रोथ रेट: ईटी ने खास बातचीत में जब डिप्टी सीएम मोदी से पूछा कि आप इस ग्रोथ रेट को कैसे कायम रख पाएंगे, तो मोदी ने कहा कि हमें विभिन्न उद्योगों और कॉर्पोरेट घरानों से करीब 1 लाख 33 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिले हैं, जो आगामी एक साल में आकार लेने लगेंगे। हालिया वित्त वर्ष के लिए हमने 16 हजार करोड़ के योजना खर्च का लक्ष्य रखा है।

आईटी पर फोकस: हम आईटी सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं और हमारी आईटी पॉलिसी पर अमल हो रहा है। इसमें आईटी कंपनियों को फायदे वाली कई पेशकश की गई हैं। बिहार से बड़े पैमाने पर आईटी प्रफेशनल दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहे हैं। अकेले बेंगलुरु में सवा लाख आईटी प्रफेशनल बिहार से हैं। ऐसे में हम बिहार को ही बेंगलुरु के बाद सबसे बड़ा आईटी डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि बेंगलुरु जैसे शहरों में रहना अब महंगा पड़ने लगा है, ऐसे में आईटी कंपनियां टियर–1 और टियर–2 शहरों जैसे पटना और जयपुर की ओर रुख कर रही हैं। राज्य में कंपनियां खोलने के लिए हमने कई आईटी कंपनियों से बात भी की है।

स्किल्ड लोगों की वापसी: अन्य स्किल्ड लेबर की उपलब्धता के बारे में पूछ जाने पर मोदी ने कहा कि बिहार में इंजिनियर, डॉक्टर और अन्य प्रफेशनल्स की बड़ी कमी थी, क्योंकि ऐसे लोगों को बाहर जॉब ढूंढना आसान लगा। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग लौट रहे हैं और इन्हें नए मौके मिल रहे हैं। श्रमिकों का अन्य राज्यों की ओर पलायन भी तेजी से घटा है। पंजाब, हरियाणा और मुंबई जैसे शहर इस कमी को महसूस भी करने लगे हैं। इन श्रमिकों को अब बिहार में ही कंस्ट्रक्शन, टूरिजम, हॉस्पिटैलिटी और रीटेल में जॉब मिल जा रही हैं और राज्य में ये सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले जॉब दिखती ही नहीं थीं। राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर की हालत खस्ता थी और कानून–व्यवस्था का बुरा हाल था। आलम यह रहा कि बीते 15 सालों में 10 हजार से ज्यादा कारोबारियों ने राज्य को छोड़ दिया। अब कोई इस स्टेट को छोड़कर नहीं जा रहा। उलटे लौट रहे हैं।

टेक सेवी बिहार 6 महीने में: उपमुख्यमंत्री मोदी ने बिहार को टेक सेवी बनाने के लिए किए गए उपायों की झलक भी दी। उनके मुताबिक, हम सभी दतरों को कंप्यूटराइज कर रहे हैं, जिससे कि ई–फाइलिंग और ई–रिटर्न जैसी प्रक्रिया और आसान हुई है। पंचायत स्तर से मुख्यालयों तक ई–गवर्नेंस सिस्टम शुरू किए गए और छह महीने में यह कोशिशें पूरी हो जाएंगी। सेल्स और एक्साइज डिपार्टमेंट में इंटर–टैक्स पेमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इसके जरिए हजारों सेंटर लोगों को मुहैया हुए हैं।

शिक्षा में फिर जगत गुरु: बिहार को एजुकेशन सेक्टर में एक बार फिर जगत गुरु बनाने के लिए 5 सालों में 19 सुपर स्पेशिऐलिटी मेडिकल कॉलेज, 23 इंजिनियरिंग कॉलेज और कुछ मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट खोलने का प्रस्ताव है। सरकार ने दो लाख शिक्षकों को भर्ती किया है और एजुकेशन सेक्टर में 10 हजार करोड़ इनवेस्ट करने की योजना है।■

बिहार में चीनी संकट के लिए केंद्र दोषी : मोदी

पटना। उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने चीनी संकट पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते कहा कि भेदभावपूर्ण नीतियों की वजह से बिहार के गरीबों को चीनी नहीं मिल सकी। चीनी ढुलाई का खर्च देने में भी केंद्र सरकार आनाकानी कर रही है।

उन्होंने बताया कि पिछले छह माह के लिए बिहार को 3 लाख 16 हजार क्विंटल चीनी मिलनी थी, लेकिन महाराष्ट्र की जर्जर चीनी मिलों से संबंध किए जाने के कारण बिहार को नई परेशानी से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चीनी के उठाव की व्यवस्था में परिवर्तन कर नई परेशानी पैदा कर दी है।

इससे पूर्व राज्य की चीनी मिलों से ही उठाव करने का प्रावधान था, लेकिन केंद्र ने नई व्यवस्था के तहत महाराष्ट्र की चीनी मिलों से उठाव का फरमान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार कोटे की चीनी का उठाव महाराष्ट्र की उन चीनी मिलों से करना है जो बंद पड़ी हैं या जर्जर अवस्था में हैं।

उन्होंने बताया कि बिहार के बीपीएल परिवारों के लिए प्रतिमाह 70 हजार 5 सौ क्विंटल चीनी का कोटा निर्धारित है लेकिन केंद्रीय नीतियों की वजह से बिहार को नुकसान उठाना पड़ रहा है। श्री मोदी ने राजद नेता लालू प्रसाद और लोजपा नेता रामविलास पासवान पर भी प्रहार किया कि मूल्य नियंत्रण के मामले में वे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उन्होंने दोनों नेताओं को नसीहत दी कि राज्य सरकार के खिलाफ आग उगलने की बजाय केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। ■

१०८ दिवसीय विश्व मंगल गो ग्राम यात्रा का नागपुर में समापन

ग्रामोदय से राष्ट्रोदय का प्रतीक है गोमाता

Xk रक्षा के लिए 108 दिन तक सम्पूर्ण देश को झकझोरने के बाद विश्व मंगल गो ग्राम यात्रा 17 जनवरी को नागपुर में सम्पन्न हो गयी। रेशिम बाग मैदान में आयोजित विशाल समापन सभा को संबोधित करते हुए सुप्रसिद्व योग गुरू बाबा रामदेव ने कहा कि गोमाता आत्मउपचार और आत्मसाक्षात्कार का आधार है और यह ग्रामोदय से राष्ट्रोदय का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि गाय कोई सांप्रदायिक प्राणी नहीं है, यह बिना किसी भेदभाव के सभी का पालन करती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आज गाय नहीं बची तो पूरी दुनिया का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।

बाबा रामदेव ने उपस्थित जनसमूह का आहवान करते हुए कहा कि सभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से गोसेवा करें। उन्होंने कहा कि प्रातःकाल गोमूत्र का सेवन अनेक बीमारियों का शमन करता है और कब्जी होने की संभावना समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि गाय अगर दूध न भी दे तो भी सिर्फ गोमूत्र और गोबर से पर्याप्त आय हो सकती है। उन्होंने सात रूपये प्रति लीटर के भाव से गोमूत्र खरीदने का भरोसा भी दिलाया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहनराव भागवत ने कहा कि एक समय था जब गाय और गांव की बात को पिछड़ी बात माना जाता था। लेकिन आज आधुनिक युग में यही मुख्य चिंतन की बात मानी जा रहा है।

उन्होंने कहा कि शहर जितना बड़ा बनेगा, उतना ही बेखबर भी बनेगा। गांव में मनुष्य मनुष्य को पहचानता है, अतः वह स्वतंत्रता, समरसता और सुख का अनुभव करता है, और नियंत्रणविहीन व्यवस्था होते हुए भी अनुशासित समाज होता है। उन्होंने गोग्राम आधारित जीवन को विकेंद्रित और प्रकृति के समीप का युगानुकुल तरीका बताया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा का उद्यापन है। केवल नारों से काम चलने वाला नहीं है। उन्होंने देशवासियों को आहवान किया कि वे गाय को जीवन में लाने के लिए दो चार कदम आगे बढ़ाएं।

विश्व मंगल गो ग्राम यात्रा के समापन समारोह के अवसर पर रेशिम बाग मैदान में मानों पूरा शहर उमड़ पड़ा। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। योग गुरू बाबा रामदेव के अलावा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत के अलावा करवीर पीठ के शंकराचार्य श्री नृसिंह भारती सरस्वती, आचार्य महासभा के अध्यक्ष स्वामी दयानंद सरस्वती, गोकर्ण पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री राघवेश्वर भारती स्वामीजी, जैन मुनि श्री पवित्र सागर महाराज, बौद्व संत भंते ज्ञान जगत महाराज, नवबौद्व संत भदंत राहुल बौधि, मौलाना बशीर कादरी आदि ने गोरक्षा के प्रति अपना संकल्प व्यक्त किया।

समापन कार्यक्रम से पूर्व यात्रा समिति के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डा एच आर नागेन्द्र, राष्ट्रीय सचिव श्री शंकरलाल एवं अन्य पदाधिकारियों ने दीक्षा भूमि जाकर भारत रत्न डा भीमराव अम्बेडकर को श्रद्वांजलि अर्पित की।

यात्रा के राष्ट्रीय सचिव श्री शंकरलाल ने बताया कि 108 दिन चली विश्व मंगल गो ग्राम यात्रा ने देश का अनवरत भ्रमण किया और दस हजार उपयात्राओं ने पूरे देश को मथ डाला। गांव–गांव, गली–गली, नगर–नगर, डगर–डगर यात्राओं का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। हिन्दू ही नहीं ईसाई और मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इसमें बढ़–चढ़कर भाग लिया। देशभर में हजारों सामाजिक संगठन इसमें सहभागी हुए।

उन्होंने बताया कि विश्व के आधुनिक इतिहास में सबसे बड़े जनमत संग्रह के रूप में यात्रा का हस्ताक्षर अभियान स्थापित हुआ है। करोड़ों लोगों ने अपने हस्ताक्षर द्वारा इस अभियान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। यह वह संख्या है जो आज से पहले किसी भी अभियान के समर्थन में नहीं जुटी।

शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य, महामंडलेश्वर, अखाडे, जैन मुनि, बौद्व भिक्षु, नामधरी संत, वाल्मिकी संत, रामसनेही सम्प्रदाय, गायत्री परिवार, बह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पातंजली योगपीठ, आर्ट ऑफ लिविंग, चिन्मय मिशन जैसे प्रतिनिधि संगठनों की सक्रिय भागीदारी भी यात्रा को यशस्वी बनाने में महत्वपूर्ण रही।

उन्होंने कहा कि यात्रा ने न केवल भारत की आस्था को झकझोरा है बल्कि देशभर में स्वावलंबन के बीज भी बोये हैं। निराश हृदयों में आशा का संचार किया है तो युवा शक्ति को आत्मविश्वास का अग्निमंत्र भी दिया है। उन्होंने कहा कि विश्व मंगल गो ग्राम यात्रा स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा और प्रभावी आंदोलन है और यह एक मौनक्रांति का सूत्रपात है।■

परंपरागत वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने की जरूरत : शिवराजसिंह चौहान

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि भारत विशाल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र रहा है। चिकित्सा के मामले में पुरातन काल से हम स्वावलंबी रहे है, क्योंकि निरोग जीवन को नियामक हमने माना है। आज परंपरागत प्रचलित वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रमाणिकता की कसौटी पर कसने और उनका विस्तार करने की आवश्यकता है। एलोपैथी के चिकित्सक इतनी संख्या में उपलब्ध नहीं है कि हम गांव–गांव तक उनकी सेवाएं सुनिश्चित कर सकें। इसलिए वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का परिष्कार कर उन्हें सम्मानित ढंग से स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए मध्यप्रदेश में दो सदस्यीय समिति का जल्दी ही गठन किया जायेगा, जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के वैज्ञानिक पहलुओं और प्रामाणिकता पर विचार करेगी और शासन को अपने निष्कर्ष से अवगत करायेगी। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ और इलेक्ट्रो होम्योपेथिक प्रेक्टेशनर्स आर्गेनाइजेशन ऑफ मध्यप्रदेश के संयुक्त प्रयास से आयोजित चिकित्सक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

पहला सुख निरोग काया माना गया है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही आत्मा और परमात्मा का आभास करा सकता है। हमारे देश में भारतीय चिकित्सा पद्धतियां बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है।

प्रदेश संगठन महामंत्री श्री माखन सिंह चौहान ने ग्रामीण वनवासी क्षेत्रों में चिकित्सा विधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित चिकित्सा विज्ञान और परंपराओं को सहेजने की आवश्यकता है, इनका विकास किया जा सकता है। अन्य देशों में वहां प्रचलित सभी चिकित्सा प्रणालियों का समानान्तर विकास हुआ है और उनसे देश की विशालता के अनुरूप उपयोगिता हासिल की गयी है। श्री माखन सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री द्वारा दो सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा का स्वागत किया और कहा कि यह प्रदेश में परंपरागत चिकित्सा की वैकल्पिक विधाओं से चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों का मान सम्मान बढायेगा। उन्होंने सुदूर ग्रामों में मानवता की सेवा में लगे वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली का अनुसरण कर रहे डॉक्टरों से मानवता की सेवा साधना के रूप में करने का आग्रह किया। चिकित्सा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक एसएस अग्रवाल, प्रदेश के चिकित्सा राज्यमंत्री महेन्द्र हार्डिया, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हितेश वाजपेयी ने भी समारोह को संबोधित किया। डॉ. हितेश वाजपेयी, डॉ. रवि वर्मा, डॉ. अभिमन्यु सिंह सहित चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री माखन सिंह चौहान, राष्ट्रीय संयोजक एसएस अग्रवाल, चिकित्सा राज्यमंत्री महेन्द्र हार्डिया ने दीप प्रज्ज्वलित किया और डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय और पितृपुरूष कुशाभाऊ ठाकरे के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री शिवराजसिंह चौहान ने चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश को स्वर्णिम राज्य बनाने के लिए सात कार्यदल गठित किये गये थे। उनकी रिपोर्ट का मंथन किया जा रहा है। सड़क, पानी, बिजली, खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने, गरीबों के कल्याण, सुशासन के अलावा स्वास्थ्य सभी के लिये हमारे मंथन का प्रमुख विषय है। पहला सुख निरोग काया माना गया है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही आत्मा और परमात्मा का आभास करा सकता है। हमारे देश में भारतीय चिकित्सा पद्धतियां बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। माना गया है कि सर्जरी का कोई विकल्प नहीं है परंतु एलोपेथी ही सर्वोत्कृष्ट है यह दावा करना न तो संभव है और न इसकी कोई प्रासंगिकता प्रतीत होती है, क्योंकि इतने विशाल देश में कोने–कोने, गांव–गांव में एलोपेथी के चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना असंभव नही तो कठिन अवश्य है। इस कमी को वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली अपना रहे चिकित्सक ही पूरा करते है। उनकी लगन, सेवा और रूग्ण मानवता के प्रति सेवा भावना को देखते हुए हम उन्हें स्थान, मान, सम्मान देंगे और उनसे अपेक्षा करेंगे कि वह पूरी प्रामाणिकता के साथ अपनी पैथी पर अटल रहकर चिकित्सा करें। घाल–मेल होने से प्रामाणिकता का क्षरण होता है। उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के चमत्कार का उल्लेख करते हुए कहा कि इस पर हमें पूरी तरह अमल करना पड़ेगा। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को सम्मान देने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि फिर भी हमें ऐसा ऐहतियात बरतना होगा कि मरीजों के साथ खिलवाड़ न हो। दो सदस्यीय समिति के सामने चिकित्सा प्रकोष्ठ और वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के पक्षधर अपना पक्ष विस्तार से रखेंगे। निष्कर्ष आने के बाद हम इस मामले को प्रदेश में वजन देने के साथ अनुशंसाओं को भारत सरकार को भी अग्रेषित करेंगे।

राष्ट्रीय संयोजक डॉ. एसएस अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य पार्टी के सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी विचार दर्शन को आगे बढ़ाना और संगठन का विस्तार करना है। चिकित्सक की पहुच जन–जन तक होती है और उसे समाज में सम्मान मिलता है वह

जनाधार के विस्तार के लिए सचेष्ट रहे : नरेन्द्र सिंह तोमर

विफ्रानसभा, लोकसभा और नगरीय निकायों के चुनाव में मिली सफलता का श्रेय संगठन के पदाफ्रिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनता को है

Hkkरतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश का यह सौभाग्य है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगरीय निकायों के चुनाव में संगठन को अच्छी सफलता मिली है और जनाधार बढ़ा है। इससे देश में प्रदेश संगठन की साख और विश्वसनीयता बढ़ी है। केन्द्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा हम पर किया है, उसे कायम रखने के लिए हमें लगातार पूर्ण निष्ठा और परिश्रम से कार्य करना है। पार्टी जनता के लिए संघर्ष करती है और समाज में सुखद परिवर्तन लाना ही पार्टी का लक्ष्य है। यह हमारी सेवा भावना से मुखरित होना चाहिए। श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भोपाल में 19 जनवरी को पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों और जिलों से आए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों, संगठन से जुड़े मंत्रियों का आभार प्रदर्शन करते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों में पार्टी ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं और विकास की ऊंचाईयां छुई हैं, उनका श्रेय आप सभी को व पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता को जाता है। प्रदेश में संगठन चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका है, जिसे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण किया जाएगा। इसमें कोई संशोधन की उम्मीद नहीं की जाना चाहिए। इसलिए पूर्व के वर्षों की तरह हम सहमति के आधार पर अच्छे लोगों को चुनें। जिससे जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतर सकें। पूर्व में सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रदेश संगठन महामंत्री माखन सिंह चौहान, प्रदेश सह संगठन महामंत्री भगवत शरण माथुर, अरविंद मेनन, प्रदेश उपाध्यक्ष विजेन्द्र सिंह सिसोदिया, अनिल माधव दवे ने दीप प्रज्ज्वलित किया और डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पं.दीनदयाल उपाध्याय और कुशाभाऊ ठाकरे के चित्रों पर माल्यार्पण किया।

प्रदेश संगठन महामंत्री माखन सिंह चौहान, भगवत शरण माथुर और अरविंद मेनन ने जिलेवार संगठन की गतिविधियों, साधारण सदस्यता, सक्रिय सदस्यता, संगठन के चुनाव की तैयारियों के संबंध में प्रगति पर चर्चा की।

प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि 31 जनवरी को प्रदेश के नगरीय निकायों के निर्वाचित पार्षदों का एक बड़ा सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया जावेगा जिसे पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी संबोधित करेंगे। उन्होंने इंदौर में 17 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यसमिति, 18–19 को राष्ट्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। परंपरा के अनुसार 18 फरवरी को इंदौर में एक विशाल रैली का आयोजन किया जावेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सभी जिलाध्यक्षों से मार्मिक अपील की कि वे संगठन के चुनाव को देखते हुए अपने–अपने जिलों में चुनाव की ऐसी तैयारी रखें, कि जिले में पहुंचने वाले चुनाव अधिकारी को दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि संगठन के चुनाव के बाद नए जिलाध्यक्ष कार्यभार संभालेंगे। हमें चाहिए कि उन्हें विरासत में साफ–सुथरा वातावरण मुहैया हो। अच्छी विरासत सौंपना ही हमारी परंपरा है। श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि 11 फरवरी को पं. दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान दिवस पर मंडल स्तर पर समर्पण दिवस का भव्य आयोजन किया जावेगा और प्रदेश से वहां वक्ता पहुंचेंगे। समर्पण दिवस से आजीवन सहयोग निधि संग्रह का अभियान शुरु किया जावेगा।

उन्होंने रायसेन और विदिशा जिलों में गत वर्ष आजीवन सहयोग निधि संग्रह का कार्य पहले ही दिन पूर्ण कर लिये जाने को एक कीर्तिमान बताया और कहा कि अन्य जिले भी इसका अनुसरण करके उदाहरण पेश कर सकते हैं। प्रदेश में महंगायी के विरोध में किए जा रहे आंदोलन से अधिक से अधिक जनता को जोड़ने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई विरोधी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, रैलियां, पीड़ित परिवारों की बस्तियों में किया जाना चाहिए क्योंकि महंगाई का दंश सबसे अधिक गरीब परिवार, अल्प आय परिवार और मध्यम वर्ग ही भुगत रहा है। ■

अपनी सहजता, सरलता और सुलभता से संगठन का विचार दर्शन जन–जन तक पहुंचाएं। उन्होंने वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली को मान्यता दिलाने की आवश्यकता रेखांकित की। साथ ही कहा कि इसमें भी सेटी फस्ट का सिद्धांत अपनाना होगा। डॉ. महेन्द्र हार्डिया ने बताया कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हमारे जीवन का प्रमुख अंग रही है। चिकित्सा प्रकोष्ठ की पहल अनुकरणीय है। उक्त अवसर पर विधायक डॉ. बाबूलाल वर्मा, डॉ. सुनील राय, महेश गुप्ता, कीर्ति वर्मा सहित अन्य चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधि और संभ्रात नागरिक भी उपस्थित थे। ■

यूपीए की गलत नीतियों के कारण बढ़ी महंगाई : ओम प्रकाश कोहली

Hkkरतीय जनता पार्टी द्वारा मंहगाई के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे आंदोलन के संदर्भ में दिल्ली प्रदेश भाजपा ने सभी मंडल इकाइयां अपने–अपने मंडल क्षेत्र में 18 से 25 जनवरी को मंहगाई विरोधी सप्ताह मनाया।

मंहगाई विरोधी सप्ताह के दौरान मंडलों में पदयात्रा, मशाल जुलूस, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ सभाएं और सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के विरूद्ध टैम्पों पर लाउडस्पीकरों से प्रचार आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए इन कार्यक्रमों में सभी निगम पार्षदों और विधायकों ने पूरी सक्रियता से भाग लिया।

प्रदेशाध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली ने 16 जनवरी को कहा कि मंहगाई आसमान छू रही है और आम आदमी बुरी तरह कराह रहा है। केन्द्र सरकार मंहगाई को रोकने में असहाय दिखाई पड़ रही है। वह कभी राज्यों को जिम्मेदारी के लिए कोसती है तो कभी वैश्विक मंदी को मंहगाई के लिए जिम्मेदार ठहराती है। यूपीए सरकार के मंत्री परस्पर विरोधी बयान दे रहे हैं। कृषि मंत्री शरद पवार के बयान मंहगाई बढ़ाने में आग में घी का काम कर रहे हैं।

प्रो. कोहली ने कहा कि भारत सरकार द्वारा गठित अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार देश में 77 फीसदी नागरिकों की आय प्रतिदिन 20 रूपए है। 20 रूपए में आम आदमी 20 से 30 रूपए किलो आटा, 30 से 35 रूपए लीटर दूध, 100 रूपए किलो अरहर की दाल और 50 से 70 रूपए किलो चीनी कैसे खरीद सकता है। सभी सब्जियों के दाम 50 रूपए किलो के आसपास है। चीनी की बढ़ती कीमतों ने देश में हाहाकार पैदा कर दिया है।

प्रो. कोहली ने कहा कि केन्द्र की गलत आर्थिक नीतियां मंहगाई के लिए जिम्मेदार हैं। यूपीए सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण ही कृषि उत्पादन घट रहा है। किसानों को उनकी लागत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यह कैसी सरकार है जो एक समय 12 रूपए किलो चीनी का निर्यात करती है और फिर उसी चीनी का 30 रूपए किलो के हिसाब से आयात करती है।

प्रो. कोहली ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही बंदरगाहों पर अनाज सड़ जाता है। पर्याप्त बफर स्टॉक निर्मित नहीं किया जाता और मुनाफाखोरों तथा जमाखोरों पर नकेल नहीं कसा जाता। अब तो हताश होकर गृहणियों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह सरकार को मंहगाई पर नियंत्रण लगाने का निर्देश दें।

प्रो. कोहली ने कहा कि शरद पवार राजनीतिक कारणों से गन्ना किसानों को नाराज करने को तैयार नहीं हैं। सरकार की गलत नीतियाँ बड़े व्यापारियों और चीनी मिलों के मालिकों को आम आदमी की कीमत पर फायदा पहुंचा रही हैं। खाद्यान्न की वायदा कारोबारी ने मंहगाई को बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा की है। प्रो. कोहली ने यह भी कहा कि डीजल और पैट्रोल की कीमतों में यूपीए के शासनकाल के दौरान हुई वृद्धि के कारण ट्रांसपोर्ट बहुत मंहगा हो गया है और उसके कारण भी आम व्यक्ति की जरूरत की वस्तुएं मंहगी हो गई हैं।

प्रो. कोहली ने कहा कि अब हालत यह हो गई है कि थोक मूल्यों पर आधारित आंकड़ों के अनुसार मंहगाई दर 17.5 प्रतिशत को पार कर गई है।

प्रो. कोहली ने मांग की कि खाद्यान्न के वायदा कारोबार को बंद किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत कर वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाए। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि और कृषक के अनुकूल नीतियां बनाई जायें और दालों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिए जायें।

प्रो. कोहली ने कहा कि मंडल स्तर पर मंहगाई विरोधी सप्ताह के कार्यक्रमों के बाद फरवरी के प्रथम सप्ताह में जिला स्तर पर मंहगाई विरोधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ■

पृष्ठ 25 का शेष....

से कुछ हिस्सा उन्हें दिया। राजमाता जी ने स्वदेश जैसे समाचार पत्रों की नींव उनकी निजी समाचार पत्र हमारी आवाज को बंदकर रखी थी। स्वदेश के विकास में उनके सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता। राजमाता जी आदर्शों की देवी थी। मर्यादाओं की मां और सामाजिकता की प्रतीक थी। उन्होंने जनसंघ से लेकर भाजपा की यात्रा में अपनी वात्सल्यता की कभी कोई कमी नहीं की।

अटलजी, आडवाणीजी उनकी सदैव इज्जत करते थे। वो बहुत साहसी थीं। सत्ता की भागीदारी के बजाय सत्ता पर निगरानी रखने में उनकी ज्यादा रूचि रहती थी। उन्होंने सदैव गलत का विरोध किया। और सही का समर्थन आज वो नहीं है लेकिन देश में भुलाए जाने के बाद भी उन्हें नहीं भूलाया जा सकता। उनका समर्पण, उनकी निष्ठा, उनकी शुचितापूर्ण जीवन, उनका संगठन प्रेम, उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता आज भी हम सबके लिए मार्गदर्शन का काम कर रही है। वे काया से भले ही हमारे बीच नहीं हो पर उनकी छाया में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। ■